● वर्ष : 17 ● अंक : 203 ● मूल्य : 02 रुपया मात्र ● पृष्ठ : 08

LKS

दैनिक लोकतंत्र की शान

लोकतंत्र का स्तंभ

RNI NO.: DELHIN / 2008 / 23928

www.loktantrakishaan.com

दिल्ली से प्रकाशित गुरुवार 14 मई 2026

अटल इच्छाशक्ति का प्रतीक पोखरण परमाणु परीक्षण

एजेंसी। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर की सराहना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए 1998 में हुए पोखरण परमाणु परीक्षणों को याद किया। उन्होंने कहा कि इन परीक्षणों ने दुनिया को भारत की अटल इच्छाशक्ति से अवगत कराया और यह साबित किया कि दबाव के बावजूद भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करता। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा, 1998 में इसी दिन भारत ने जो परमाणु परीक्षण किए थे, उनसे दुनिया को पता चला कि हमारे देश की इच्छाशक्ति कितनी अटल है! 11 मई के टेस्ट के बाद पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन हमने दिखाया कि कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती। उन्होंने एक संस्कृत श्लोक भी साझा कियाः एवं परस्परापेक्षा शक्तिशक्तिमतोः स्थिता। न शिवेन विना शक्तिर्न शक्त्या विना शिवः।। इस श्लोक का अर्थ समझाते हुए उन्होंने कहा कि शक्ति और सामर्थ्य एक-दूसरे के पूरक होते हैं। केवल क्षमता होना पर्याप्त नहीं, उसे कार्यरूप देने वाली शक्ति भी आवश्यक है, और शक्ति भी तभी सार्थक होती है जब उसके पीछे समर्थ आधार हो। जैसे शिव और शक्ति का अस्तित्व परस्पर अविभाज्य माना गया है, वैसे ही सामर्थ्य और ऊर्जा के समन्वय से ही सृजन, प्रगति और सफलता संभव होती है। गौरतलब है कि 13 मई 1998 का दिन भी भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी दिन राजस्थान के पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के तहत भारत ने दो और सफल परमाणु परीक्षण किए थे, जिन्हें शक्ति-4 और शक्ति-5 नाम दिया गया था। ये परीक्षण 11 मई 1998 को हुए पहले तीन परीक्षणों की श्रृंखला का ही आगे का हिस्सा थे, जिन्होंने देश की सामरिक क्षमताओं को एक नई ऊंचाई दी। इन परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को और मजबूत करना था। यह भी बताया गया कि सभी परीक्षण भूमिगत और पूरी तरह नियंत्रित थे, जिससे किसी भी तरह की रेडियोएक्टिविटी बाहर नहीं फैली। इन सफल अभियानों से मिले आंकड़ों का उपयोग कंप्यूटर सिमुलेशन और भविष्य की परमाणु तकनीक को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस पूरे साहसिक अभियान का नेतृत्व तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। इन सफल परीक्षणों के बाद भारत को दुनिया में एक परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली, जिसने देश की सुरक्षा और संप्रभुता को और मजबूत किया।

केंद्र सरकार ने 37,500 करोड़ की सतही कोयला गैसीकरण योजना को दी मंजूरी

एजेंसी। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने सतही कोयला (लिग्नाइट) गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 37 हजार 500 करोड़ रुपये की लागत वाली योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत देश में सतही कोयला (लिग्नाइट) को गैस में बदलने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन सतही कोयले का गैसीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करने का है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में इसे बहुत बड़ा फैसला बताते हुए कहा कि भारत के पास लगभग 200 साल का कोयला भंडार है और अब इसका उपयोग गैस बनाने में किया जाएगा। इस योजना से लगभग 3 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की संभावना है। गैसीकरण से देश की ऊर्जा निर्भरता कम होगी और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), यूरिया, अमोनिया और मीथेनॉल जैसे उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम होगी। उल्लेखनीय है कि भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े कोयला भंडारों में से एक है, जिसमें लगभग 401 अरब टन कोयला और 47 अरब टन लिग्नाइट शामिल है। कोयला देश की ऊर्जा खपत का 55 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पूरा करता है। गैसीकरण से कोयला और लिग्नाइट को 'सिंथेसिस गैस' (सिंगैस) में बदला जाता है, जिसका उपयोग ईंधन और रसायन बनाने में किया जाता है। इससे भारत को एलएनजी, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनिया, कोकिंग कोल और मीथेनॉल जैसे उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने बताया कि योजना के तहत नए सतही कोयला (लिग्नाइट) गैसीकरण संयंत्रों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। संयंत्र और मशीनरी की लागत का अधिकतम 20 प्रतिशत तक वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा। परियोजनाओं का चयन पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से होगा।

ज्वलंत मुद्दा | संपादकीय

भारतीय अर्थ व्यवस्था का महासंकट

भारतीय अर्थ व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार तेज विकास, बढ़ते बुनियादी ढांचे और विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा करती रही है। अब इस दावे की पोल खुलती चली जा रही है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने भारत की अर्थव्यवस्था में आने वाले महा संकट का संकेत किया है, उन्होंने सरकार के चमकदार दावों के पीछे छिपी सच्चाई को उजागर किया है। उनका मानना है, भारत की अर्थव्यवस्था दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक संगठित क्षेत्र, जो कॉरपोरेट और शेयर बाजार की वृद्धि को अर्थव्यवस्था में दिखाता है, दूसरा असंगठित क्षेत्र, जहां देश की लगभग 94 प्रतिशत कार्यशक्ति काम करती है, जो लगातार संकट में है।

उसकी वास्तविकता सरकार उजागर नहीं करती है। प्रो. अरुण कुमार के अनुसार सबसे बड़ा संकट "मांग मे कमी" आने का है। जब आम लोगों की आय घटती है, रोजगार कम होता है, उस समय सबसे पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था और असंगठित क्षेत्र कमजोर होता है। बाजार में मांग घटती है। इसका सीधा असर उद्योगों के उत्पादन, कारोबार और निवेश पर पड़ता है। यही कारण है कि ऊंची जीडीपी वृद्धि के बावजूद देश मे रोजगार का सृजन नहीं हो रहा। उल्टे नौकरियां जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में बढ़ती बेरोजगारी और असमानता को लेकर कई वर्षों से चिंता जताई जा रही है। अर्थशास्त्री नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना महामारी के बाद असंगठित क्षेत्र को जो नुकसान हुआ है उसके बारे में कई बार अपनी चिंता पिछले वर्षों में व्यक्त कर चुके हैं। सरकार ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। छोटे व्यापारी, कुटीर उद्योग, किसान और दिहाड़ी मजदूर सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। प्रो. अरुण कुमार का दावा है, सरकारी आंकड़े इस वास्तविक स्थिति को छुपाने का काम करते हैं।

आंकड़ों को बदल देते हैं। सही मायने में कहा जाए तो सरकार आंख बंद करके जीडीपी और अर्थव्यवस्था को बेहतर बताकर अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है। सरकार ने जीडीपी मापन की वर्तमान प्रणाली में असंगठित क्षेत्र की गिरावट को सही ढंग से वास्तविक स्थिति को शामिल नहीं किया है। जिसके कारण देश की आर्थिक स्थिति कागजों में कुछ और है, और वास्तविक स्थिति कुछ और है। वर्तमान स्थिति यह है, शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर है। बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अर्थव्यवस्था में जो बदलाव आए हैं उसके कारण भारत सहित वैश्विक स्तर पर लोगों की नौकरियां जा रही हैं। भारत के लगभग 80 करोड लोग मुफ्त राशन पर निर्भर हैं। भारत की अर्थव्यवस्था वास्तव में मजबूत होती, तो रोजगार और लोगों की आय में यह परिवर्तन दिखाई देता। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्र की जो मांग पहले बढ़ रही थी, अब तेजी के साथ घट रही है। महंगाई और आय नहीं होने से मांग में निरंतर कमी आ रही है। युवाओं में बेरोजगारी और कृषि संकट भारत के तथाकथित विकास मॉडल और अर्थव्यवस्था को उजागर कर रहे हैं। अरुण कुमार सहित कई अर्थशास्त्रियों ने लगातार चिंता व्यक्त की है।

सैयद जकी हैदर | सम्पादक/प्रकाशक
MOBE NO.**9911371802**
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER**786**@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

एयर इंडिया ने तीन महीनों के लिए की कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द

नई दिल्ली। मध्य पूर्व संकट के कारण जेट ईंधन की बढ़ती कीमतों के चलते एयर इंडिया ने जून की शुरुआत से तीन महीनों के लिए कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित करने का फैसला लिया है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दिल्ली से जिन अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में कमी की गई है उनमें शिकागो और नेवार्क, सिंगापुर और शंघाई जैसे प्रमुख गंतव्य शामिल हैं। इसके अलावा, एयर इंडिया ने सैन फ्रांसिस्को, पेरिस और टोरंटो जैसे गंतव्यों के लिए भी उड़ानें कम कर दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल मिलाकर एयरलाइन ने रोज करीब 100 उड़ानों को कम किया है। एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने पिछले सप्ताह कहा था कि भू-राजनीतिक तनाव के बीच ईंधन की बढ़ती कीमतों के चलते एयरलाइन अंतरराष्ट्रीय सेवाओं में कटौती जारी रखेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बढ़ते वित्तीय दबाव और परिचालन संबंधी चुनौतियों का सामना करते हुए, एयर इंडिया ने अपने आंतरिक अनुपालन और लागत नियंत्रण उपायों को और कड़ा कर दिया है। एयरलाइन ने पिछले तीन सालों में नैतिक कदाचार और नीतिगत उल्लंघनों के लिए 1,000 से ज्यादा कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। यह खुलासा विल्सन ने पिछले सप्ताह कर्मचारियों के साथ एक टाउन हॉल बैठक में किया। विल्सन ने कर्मचारियों को बताया कि एयरलाइन ने कई उल्लंघनों में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है।

देश में बड़ी बिल्लियों के संरक्षण पर पांच थीम आधारित कार्यक्रम आयोजित करेगी केंद्र सरकार

नई दिल्ली। केंद्र सरकार देश में बड़ी बिल्लियों के संरक्षण को बढ़ावा देने और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के उद्देश्यों को सामने रखने के लिए पांच बिंदुओं की थीम आधारित कार्यक्रम आयोजित करेगी। इन कार्यक्रमों में बाघ, एशियाई शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता संरक्षण से जुड़े प्रयासों, उपलब्धियों और चुनौतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि ये कार्यक्रम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन-2026 से पहले देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों का आयोजन गुजरात के गिर, मध्य प्रदेश के भोपाल, ओडिशा के भुवनेश्वर, सिक्किम के गंगटोक और महाराष्ट्र के चंद्रपुर में किया जाएगा। गिर में एशियाई शेर संरक्षण कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें प्रोजेक्ट लायन, वैज्ञानिक निगरानी प्रणाली, आवास सुधार और मालधारी समुदाय की भूमिका को रेखांकित किया जाएगा। चंद्रपुर में बाघ संरक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रोजेक्ट टाइगर, वन्यजीव गलियारों की सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणाली और मानव-बाघ संघर्ष कम करने के प्रयासों को प्रदर्शित किया जाएगा।

मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक का निधन, यादव परिवार को बड़ा सदमा

एजेंसी। लखनऊ

उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार और समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का बुधवार तड़के निधन हो गया। 38 वर्षीय प्रतीक यादव भाजपा नेत्री और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति थे। इस दुखद समाचार से लखनऊ से लेकर सैफई तक शोक की लहर दौड़ गई है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, प्रतीक यादव पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। बुधवार भोर में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सुबह लगभग छह बजे लखनऊ के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज बताया जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारणों की पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम कराया जाने का फैसला किया गया है। प्रशासन ने चार डॉक्टरों के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए हैं। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे। सक्रिय राजनीति से दूर रहने वाले प्रतीक रियल एस्टेट और फिटनेस व्यवसाय से जुड़े थे। उन्होंने लंदन की लीड्स यूनिवर्सिटी से एमबीए किया था और लखनऊ में उनका प्रसिद्ध जिम द फिटनेस प्लैनेट संचालित होता था। प्रतीक और अपर्णा यादव का विवाह दिसंबर 2011 में हुआ था, जो स्कूल के दिनों की उनकी लंबी दोस्ती का परिणाम था।

नई दिल्ली में ब्रिक्सः विदेश मंत्रियों की बैठक का आगाज

एजेंसी। नई दिल्ली

ब्रिक्स बैठक के लिए उज्बेकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान के नेता पहुंचे दिल्ली

नई दिल्ली में 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। भारत इस साल 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, और इसी कड़ी में इस दो दिवसीय आयोजन में सदस्य देशों तथा कई आमंत्रित राष्ट्रों के वरिष्ठ राजनयिकों का जमावड़ा लगा है। बैठक का उद्देश्य वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करना। इस बैठक में ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया के विदेश मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। संयुक्त अरब अमीरात का प्रतिनिधित्व उप-विदेश मंत्री स्तर पर होने की उम्मीद है, जबकि चीन के शेरपा का प्रतिनिधिमंडल इसमें शिरकत करेगा। दक्षिण अफ्रीका के अंतरराष्ट्रीय संबंध मंत्री रोनाल्ड ओजी लामोला मंगलवार को और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगिओनो बुधवार को नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। ईरान ने भी अपने विदेश मंत्री अब्बास अराघची के शामिल होने की सूचना दी है, हालांकि क्षेत्रीय स्थिति के कारण उनकी योजना में बदलाव संभव है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी जल्द पहुंचने वाले हैं, जहां वे अपने भारतीय समकक्ष एस. जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेगा। उल्लेखनीय है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी व्यस्तता के चलते बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं; उनके स्थान पर भारत में चीन के राजदूत शी फीहोंग प्रतिनिधित्व करेंगे। चीन ने भारत द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए समर्थन व्यक्त किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, 14 मई को विदेश मंत्रियों का आगमन भारत मंडपम में हुआ, जिसके बाद पहले सत्र की शुरुआत हुई। दिन के एक बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी मंत्रियों की संयुक्त मुलाकात हुई और शाम को विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर की तरफ से रात्रिभोज का आयोजन किया गया। 15 मई को तीसरे सत्र के साथ यह बैठक संपन्न होगी। इससे पहले 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 9 सितंबर 2021 को भारत में आयोजित किया गया था, जिसका थीम निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा-ब्रिक्स सहयोग था।

पाकिस्तान से बातचीत होते रहना चाहिएः संघ

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने भारत और पाकिस्तान के बीच जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए नागरिक समाज की भूमिका और आपसी संवाद पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच तनाव कम करने का सबसे प्रभावी माध्यम लोगों के बीच आपसी संपर्क है और बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। होसबाले ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व ने भारत का विश्वास पूरी तरह खो दिया है। ऐसी स्थिति में अब समय आ गया है कि दोनों देशों का नागरिक समाज, शिक्षाविद, खिलाड़ी, वैज्ञानिक और सामुदायिक नेता आगे आएं और नेतृत्व करें। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अंततः नागरिक समाज के रिश्ते ही काम आएंगे क्योंकि दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध हैं और हम कभी एक ही राष्ट्र रहे हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने 26/11, पुलवामा और पहलगाम जैसे हमलों का जिक्र किया।

तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय ने जीता विश्वास मत

बहुमत से 36 ज्यादा मिले मत

चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बुधवार को राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। हालिया चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने सदन के पटल पर अपनी मजबूती साबित कर दी। 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता थी, जिसके मुकाबले विजय सरकार के पक्ष में 144 वोट पड़े। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री विजय ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई (एम), वीसीके और आईयूएमएल जैसे प्रमुख गठबंधन सहयोगियों का औपचारिक समर्थन प्राप्त हुआ। हालांकि, सदन में सबसे बड़ा उलटफेर तब देखने को मिला जब मुख्य विपक्षी दल एआईएडीएमके के भीतर मची कलह खुलकर सामने आ गई। एसपी वेलुमणि और सीवी षणमुगम के नेतृत्व वाले बागी गुट ने मुख्यमंत्री विजय के समर्थन में वोट करने का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार, एआईएडीएमके के 47 में से करीब 30 विधायकों ने पार्टी नेतृत्व से बगावत की, जिनमें से कम से कम 25 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया।

एन. रंगासामी ने पांचवीं बार संभाली पुडुचेरी की कमान

एनडीए सरकार की वापसी, ए. नमशिवायम और मल्लाडी कृष्णा राव ने भी ली मंत्री पद की शपथ

एजेंसी। पुडुचेरी

पुडुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने एक बार फिर सत्ता में वापसी करते हुए नई सरकार का गठन कर लिया है। अनुभवी नेता और ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस (एआईएनआरसी) के संस्थापक एन. रंगासामी ने बुधवार को लगातार दूसरी बार और कुल पांचवीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजनिवास में आयोजित भव्य समारोह में उपराज्यपाल के. कैलाशनाथन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री रंगासामी के साथ एआईएनआरसी के वरिष्ठ नेता मल्लाडी कृष्णा राव तथा भाजपा नेता ए. नमशिवायम ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के वरिष्ठ नेता बी.एल. संतोष सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री एन. रंगासामी ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें पांचवीं बार मुख्यमंत्री बनने पर अत्यंत खुशी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार राज्य के विकास और जनता की भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि सरकार प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने, नई विकास योजनाएं लागू करने और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में काम करेगी। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार किया जाएगा। हाल ही में संपन्न हुए 2026 के पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 30 में से 17 सीटों पर जीत हासिल की।

अनुपालन-आधारित' से 'अधिकार-आधारित' संस्कृति की ओर बढ़ना चाहिएः न्यायमूर्ति रामासुब्रमणियन

एजेंसी। नई दिल्ली

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन ने कहा कि हमें 'अनुपालन-आधारित' दृष्टिकोण से हटकर 'अधिकार-आधारित' संस्कृति की ओर बढ़ना चाहिए। न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन ने नई दिल्ली स्थित अपने परिसर में 'प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षाः सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी' विषय पर आयोजित एक कोर ग्रुप बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में नीतिगत बदलावों के बजाय व्यावहारिक कार्यान्वयन और प्रणालीगत सुधारों पर गहन चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए रामासुब्रमणियन ने कहा, "प्रवासी श्रमिक अन्य श्रमिकों की तुलना में अधिक संवेदनशील हैं। भाषा की बाधा और स्थायी आवास की कमी उन्हें संगठित होने से रोकती है। इसलिए अब समय आ गया है कि सिर्फ 'आदेशों का पालन' करना काफी नहीं है, हमें ऐसी संस्कृति अपनानी चाहिए जहां हर व्यक्ति के 'अधिकारों का सम्मान' हो। उन्होंने 1979 के प्रवासी श्रमिक कानून की खामियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि अक्सर नियोक्ता कानूनी सुरक्षा से बचने के लिए श्रमिकों को पात्रता अवधि (240 दिन) से पहले ही अवकाश पर भेज देते हैं। आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति (डॉ.) बिद्युत रंजन सारंगी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यदि प्रवासी श्रमिकों को समय पर पारिश्रमिक नहीं मिलता, तो उनके घर छोड़ने का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि न केवल श्रमिकों बल्कि उनके साथ आए परिवार के सदस्यों का भी डेटाबेस बनाया जाना चाहिए ताकि उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। महासचिव भरत लाल ने वैश्विक और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रवासियों के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि भारत की लगभग 28.9 प्रतिशत आबादी प्रवासी श्रमिकों की है। कल्याणकारी उपायों से कारखाने के श्रमिकों की कार्यक्षमता में 1.38 गुना वृद्धि होती है।

एनटीए को हटाकर नई पारदर्शी, मजबूत और स्वायत्त संस्था बनाई जाए

नई दिल्ली। नीट यूजी 2026 परीक्षा को लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (एफएआईएमए) ने कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और बड़े सुधारों की मांग की है। एफएआईएमए ने कहा कि पिछले कुछ समय से नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं। खासकर पेपर लीक, तकनीकी गड़बड़ियों और पारदर्शिता की कमी जैसी शिकायतों ने लाखों छात्रों और अभिभावकों का भरोसा कमजोर किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसी वजह से संगठन ने मांग की है कि नीट यूजी 2026 की पूरी प्रक्रिया को या तो दोबारा कराया जाए या फिर इसे न्यायिक निगरानी में कराया जाए, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। याचिका में सबसे बड़ा मुद्दा एनटीए को लेकर उठाया। एफएआईएमए ने कहा कि पिछले कुछ सालों में एनटीए की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। इसलिए या तो इसे पूरी तरह हटाया जाए या फिर इसका पुनर्गठन करके एक नई, ज्यादा पारदर्शी, तकनीकी रूप से मजबूत और स्वायत्त संस्था बनाई जाए।

Mfg & mkt by.. ANGEN PHARMACEUTICALS (OPC) PRIVATE LIMITED

Distributorship ke liye contact Karen .
(9315755133 / ya email Karen)
angenpharmaceuticals@gmail.com

ख़ास ख़बर

टीवीके विधायक सेतुपति को राहत, सुप्रीम कोर्ट की मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर रोक

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) के विधायक सिनीवासा सेतुपति को विधानसभा में विश्वास मत के दौरान मतदान करने से रोकने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मद्रास उच्च न्यायालय की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है। सेतुपति के निर्वाचन को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। सेतुपति की जीत महज एक वोट से हुई है। सेतुपति ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में तिरुपत्तुर से एक वोट से जीत हासिल की थी। सेतुपति के निर्वाचन को द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (डीएमके) उम्मीदवार केआर पेरियाकरुप्पन ने मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। पेरियाकरुप्पन ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एक पोस्टल बैलट की गिनती इसलिए नहीं की गई, क्योंकि वो दूसरे विधानसभा सीट के लिए भेज दिया गया था।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कृषि आय पर टैक्स लगाने की मांग वाली याचिका सुनने से किया इनकार

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में कृषि से होने वाली आय पर टैक्स लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोर्ट टैक्स नीति के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और ये सरकार का नीतिगत मामला है। कोर्ट ने कहा कि वो न्यायिक आदेश के जरिये सरकार को ये नहीं कह सकती है कि वो टैक्स पर किस किस्म का कानून बनाए, ये काम विधायिका का है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई बार याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या कोर्ट इस तरह का आदेश पारित कर सकती है कि सरकार कानून बनाए।याचिका आकाश गोयल ने दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से वकील कुमार उत्कर्ष ने कहा कि कृषि से होने वाली आय पर टैक्स भरने से छूट मिलती है जबकि कई लोगों की कृषि से होने वाली आय काफी ज्यादा होती है। ऐसा करने से वित्तीय असमानता पैदा होती है। याचिका में कहा गया था कि कृषि और गैर-कृषि आय का वर्गीकरण मनमाने तरीके से किया गया है। याचिका में कहा गया था कि सैलरी पाने वाले कर्मचारियों, व्यापारी और प्रोफेशनल्स टैक्स भरते हैं लेकिन महज कृषि आय घोषित कर देने से बड़ी आय वालों को भी टैक्स भरने से छूट मिल जाती है। याचिका में कहा गया था कि ऐसा संविधान के अनुच्छेद 14, 38 और 265 का उल्लंघन है। टैक्स में ऐसी छूट पक्षपातपूर्ण वर्गीकरण है और टैक्स भरने वालों के साथ पक्षपात है।

नितिन गडकरी पुणे में बस से करेंगे परियोजनाओं का निरीक्षण

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 14-15 मई को संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज पालखी मार्ग परियोजनाओं के निरीक्षण के दौरान बस यात्रा करेंगे। इस यात्रा में अधिकारी, पत्रकार और सुरक्षा कर्मी भी बस से उनके साथ सफर करेंगे। गडकरी ने आधिकारिक पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री के सुझाव के अनुसार ईंधन की खपत कम करना राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा के हित में आवश्यक है। बस से यात्रा करने से न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि यातायात प्रबंधन और जनसुविधा भी बेहतर होगी।इसी कारण उन्होंने दौरे के दौरान सुरक्षा काफिले में तैनात वाहनों की संख्या सामान्य तैनाती की तुलना में 50 प्रतिशत तक घटाने का निर्देश दिया है। पत्र में पुणे शहर के पुलिस आयुक्त, पुणे, सतारा और सोलापुर के जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भी इसकी प्रति भेजी गई है। उन्होंने पत्र में कहा कि इस निर्णय को लागू करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं ताकि कार्यक्रम सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

सीबीआई ने त्रिपुरा चिटफंड घोटाले में फरार आरोपित संजीत चक्रवर्ती को कोलकाता से दबोचा

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने त्रिपुरा के बहुचर्चित चिटफंड घोटाले में वांछित आरोपित संजीत चक्रवर्ती को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित पर लगभग 7.75 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है। सीबीआई ने बताया कि संजीत चक्रवर्ती कोलकाता स्थित कॉस्मिक नेगोशिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड का चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर था। वर्ष 2013 में त्रिपुरा पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के बाद से फरार था। त्रिपुरा सरकार और केंद्र सरकार की अधिसूचनाओं के बाद सीबीआई ने इन मामलों की जांच अपने हाथ में ली थी।जांच के बाद वर्ष 2015 में पहले मामले में संजीत चक्रवर्ती और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था। इसमें लगभग 7.48 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है। दूसरे मामले में वर्ष 2024 में आरोपपत्र दाखिल किया गया। इसमें लगभग 27.13 लाख रुपये की ठगी का आरोप है। दोनों मामलों में संजीत चक्रवर्ती को आरोपपत्र में फरार आरोपी के रूप में दर्शाया गया था।सीबीआई के अनुसार आरोपी 2013 से लगातार गिरफ्तारी से बचता रहा। एजेंसी ने फील्ड वेरिफिकेशन, तकनीकी और निगरानी, कॉल डिटेल रिकॉर्ड विश्लेषण और ओएसआईएनटी के आधार पर जानकारी जुटाई। इसके बाद उसे कोलकाता में चिन्हित कर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपित को कोलकाता की अदालत से ट्रांजिट वारंट हासिल करने के बाद त्रिपुरा लाया जाएगा और सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। मामले की आगे की जांच जारी है।

सीबीआई ने उत्तराखंड के एलयूसीसी चिटफंड घोटाले में पांच आरोपितों को किया गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उत्तराखंड के लोनी अर्बन बहु-राज्यीय ऋण और बचत सहकारी समिति (एलयूसीसी) चिटफंड घोटाले में पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में मुख्य सरगना सुशील गोखरू के साथ राजेंद्र सिंह बिष्ट, तरुण कुमार मौर्य, गौरव रोहिल्ला और ममता भंडारी शामिल हैं। इन्हें देश के अलग-अलग स्थानों से पकड़ा गया। सीबीआई ने बताया कि मामला एलयूसीसी से जुड़ा है। वर्ष 2025 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस घोटाले से संबंधित सभी प्राथमिकी सीबीआई को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। इसके बाद सीबीआई ने 26 नवंबर 2025 को भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता, उत्तराखंड जमाकर्ताओं के हित संरक्षण अधिनियम और अनियमित जमा योजनाओं पर रोक लगाने वाले अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। जांच में सामने आया है कि इस घोटाले में राज्य के एक लाख से अधिक निवेशकों को विभिन्न अनियमित जमा योजनाओं में पैसा लगाने के लिए लालच दिया गया। कुल निवेश लगभग 800 करोड़ रुपये का अनुमानित है, जिसमें से आंशिक भुगतान किया गया, लेकिन धोखाधड़ी की राशि 400 करोड़ रुपये से अधिक है। सीबीआई ने बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपित समीर अग्रवाल और उनकी पत्नी सानिया अग्रवाल विदेश भाग गए हैं। इनके खिलाफ नोटिस और परिपत्र जारी किए गए हैं। एजेंसी ने तकनीकी निगरानी और स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर विशेष टीम गठित कर आरोपितों को पकड़ने की कार्रवाई की।

दिल्ली में शहर के बाहरी क्षेत्रों में विकसित होंगे लॉजिस्टिक्स केंद्र, शहर की भीड़भाड़, प्रदूषण में आएगी कमी

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार लॉजिस्टिक्स एवं वेयरहाउसिंग नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। यह नीति राजधानी में माल ढुलाई एवं आपूर्ति प्रणाली को अधिक कुशल, तेज और कम लागत वाला बनाने के साथ-साथ व्यापार को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। नीति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में माल परिवहन से होने वाली भीड़भाड़ को कम करना, प्रदूषण घटाना और राजधानी को एक आधुनिक, कुशल और पर्यावरण अनुकूल लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करना है।नीति के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित प्लानिंग, रियल-टाइम ट्रैकिंग और डिजिटल फ्रेट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किए जाएंगे। इससे माल ढुलाई की योजना, रूट ऑप्टिमाइजेशन और डिलीवरी शेड्यूलिंग अधिक सटीक और कुशल बनेगी, जिससे लागत में कमी और समय की बचत होगी।मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार नीति के तहत शहर के बाहर परिधीय क्षेत्रों में शहरी समेकन एवं लॉजिस्टिक्स वितरण केंद्र (यूसीएलडीसी) विकसित किए जाएंगे, जहां बड़े स्तर पर आने वाले माल को एक स्थान पर एकत्र कर आवश्यकता के अनुसार शहर के भीतर भेजा जाएगा। साथ ही बाजार स्तर के गोदाम और सूक्ष्म पूर्ति केंद्र विकसित किए जाएंगे, जिससे सामान की अंतिम चरण तक डिलीवरी तेज और व्यवस्थित होगी। अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) का आधुनिकीकरण किया जाएगा तथा लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर, ट्रक टर्मिनल और पार्किंग हब विकसित किए जाएंगे। मंडियों के पास कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, जिससे भंडारण और परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी और शहर के भीतर ट्रैफिक दबाव कम होगा। नीति में पर्यावरण संरक्षण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा और अंतिम चरण तक सामान पहुंचाने की व्यवस्था को स्वच्छ बनाया जाएगा। सौर ऊर्जा आधारित वेयरहाउसिंग और ऊर्जा दक्ष ढांचे को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी) के माध्यम से माल की आवाजाही की वास्तविक समय पर निगरानी और बेहतर प्रबंधन संभव होगा। आधुनिक तकनीकों के उपयोग से माल ढुलाई और डिलीवरी प्रणाली अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। इस नीति से ई-कॉमर्स, वस्त्र, निर्माण सामग्री, फल एवं सब्जियां और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। बेहतर भंडारण और वितरण व्यवस्था से उद्योगों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। साथ ही, तीसरा पक्ष लॉजिस्टिक्स सेवाओं (3पीएल) को भी मजबूती मिलेगी। वर्तमान में लगभग 61 प्रतिशत वेयरहाउसिंग की मांग ई-कॉमर्स क्षेत्र से आती है, जिसे ध्यान में रखते हुए यह नीति आधुनिक पूर्ति अवसंरचना में बड़े निवेश को आकर्षित करेगी। इस नीति से वेयरहाउसिंग, परिवहन, लॉजिस्टिक्स पार्क और कोल्ड चेन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे। साथ ही पैकेजिंग, आईटी आधारित सेवाओं और अन्य सहायक क्षेत्रों में भी रोजगार बढ़ेगा। सरकार द्वारा कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिनमें प्रति कर्मचारी 5,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे एक प्रशिक्षित कार्यबल तैयार होगा। लॉजिस्टिक्स अवसंरचना के विकास पर 50 प्रतिशत तक की पूंजी सब्सिडी (अधिकतम 50 करोड़ रुपये) दी जाएगी। साथ ही ब्याज सब्सिडी और बिजली शुल्क में राहत से लागत कम होगी। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। नीति के तहत सिंगल विंडो प्रणाली को मजबूत किया जाएगा, जिससे सभी अनुमतियां एक ही मंच पर उपलब्ध होंगी। वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स गतिविधियों को 24×7 संचालित करने की सुविधा दी जाएगी तथा लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा। 'मास्टर प्लान दिल्ली 2041' के तहत थोक बाजारों को चरणबद्ध तरीके से शहर के बाहर स्थानांतरित किया जाएगा तथा लॉजिस्टिक्स हब के लिए भूमि की शीघ्र पहचान और आवंटन सुनिश्चित किया जाएगा। यह नीति दिल्ली के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में व्यापक सुधार लाएगी। इससे आपूर्ति शृंखला मजबूत होगी, उद्योगों को गति मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा और निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह नीति दिल्ली की लॉजिस्टिक्स दक्षता को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मजबूत करेगी और राज्यों की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस मापने वाली एलईएडीएस (लीड्स) रैंकिंग में सुधार लाने में सहायक होगी। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, पारदर्शी प्रक्रियाओं और डिजिटल एकीकरण के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नई गति मिलेगी, जिससे निवेशकों के लिए दिल्ली अधिक आकर्षक गंतव्य बनेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह नीति दिल्ली को एक आधुनिक, कुशल और पर्यावरण अनुकूल लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करेगी।

NEET पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है, और इस नाकामी की जिम्मेदार BJP सरकार है: उदय भानु चिब

लोकतंत्र की शान

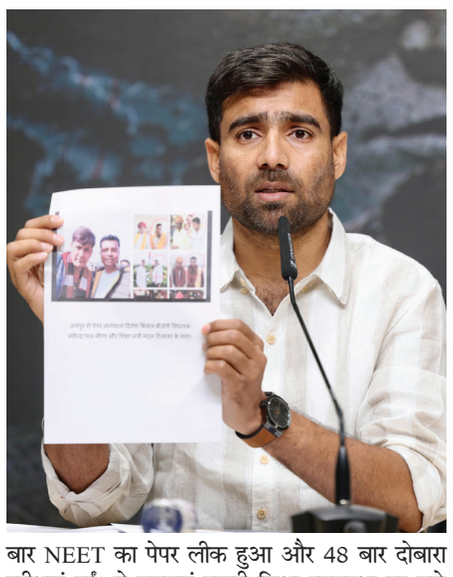

नई दिल्ली : भारतीय युवा कांग्रेस ने आज NEET पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्री अक्षय लाकड़ा के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यालय से रायसीना रोड कि ओर जा रहे थे कि पुलिस ने उनको बैरिकेडिंग कर रोक दिया। इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने कहा कि पीएम मोदी दो देशों के बीच का युद्ध रुकवा देते हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पा रहे हैं। जब से NTA बनी है, तब से लगातार पेपर लीक हुए हैं, मेरिट को लेकर सवाल उठे और अदालतों ने भी इस पर संज्ञान लिया। इससे पहले विश्वविद्यालय, राज्य सरकार परीक्षाएं खुद कराती थीं, लेकिन अब NTA के जरिए BJP हमारे बच्चों का भविष्य अंधेरे में धकेल रही है। आज BJP ने ऐसा करप्ट सिस्टम बना दिया है, जहां अमीरों के बच्चे पास होंगे, सीट लेंगे और नौकरी पा जाएंगे। मगर गरीबों के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्री अक्षय लाकड़ा ने यह भी कहा कि NEET पेपर लीक में BJP के बड़े-बड़े नेताओं का सामने आया है, जो खुद कोचिंग संस्थान चलाते हैं। NEET का पेपर रद्द करना समस्या का हल नहीं है।आखिर क्या कारण है कि पिछले 10 साल में 89 पेपर लीक हुए हैं, 4 बार NEET का पेपर लीक हुआ और 48 बार दोबारा परीक्षाएं हुईं। ये घटनाएं हमारी शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है। हमारे छात्र जान चुके हैं कि मोदी सरकार नाकाम है। इसे लेकर छात्रों में भारी हताशा है। आज BJP छात्रों का जीवन खराब कर रही है। हम मिलकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और छात्रों को न्याय दिलाएंगे।

मिलिंद सोमन बने टेस्टी निबल्स के ब्रांड एंबेसडर, केन्ड टूना पर फोकस करते हुए पूरे भारत में विस्तार की तैयारी

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली : एचआईसी-एबीएफ (HIC-ABF) स्पेशल फूड्स के मशहूर ब्रांड 'टेस्टी निबल्स' ने फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन को अपना नया ब्रांड एंबेसडर बनाया है। इसके साथ ही कंपनी ने पूरे भारत में अपने बिजनेस को तेजी से फैलाने की योजना भी पेश की है। इस साझेदारी के जरिए कंपनी का फोकस सेहतमंद और आसानी से तैयार होने वाले प्रोडक्ट्स पर होगा। ब्रांड के लिए यह एक बड़ी शुरुआत है, क्योंकि अब वे अपने सबसे खास प्रोडक्ट डिब्बाबंद टूना मछली (केन्ड टूना), के साथ पूरे देश के बाजारों में अपनी पहचान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान टेस्टी निबल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर, चेरियन कुरियन ने कहा कि, "टेस्टी निबल्स में हमारा हमेशा से यह मानना रहा है कि फूड इंडस्ट्री का भविष्य हेल्थ, सुविधा और भरोसे के मेल में है। मिलिंद सोमन के हमारे साथ जुड़ने से, हम टूना मछली को भारतीयों के रोजमर्रा के खाने का हिस्सा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। भारत में अभी बहुत कम लोग टूना खाते हैं, और यह हमारे पास एक बड़ा मौका है कि हम लाखों परिवारों को प्रोटीन का एक शुद्ध और हाई-क्वालिटी विकल्प दे सकें।" इस कार्यक्रम में सुनील पी कृष्णन, वाइस प्रेसिडेंट (सेल्स) और मनोज टीपी, सीनियर मैनेजर- की अकाउंट्स भी मौजूद रहे। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर्स, इंडस्ट्री से जुड़े प्रमुख लोग, ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। चेरियन कुरियन ने कहा कि, "दुनियाभर में टूना एक लोकप्रिय प्रोटीन सोर्स है, लेकिन भारत में प्रति व्यक्ति इसका इस्तेमाल अभी भी काफी कम है। 1.4 अरब से ज्यादा आबादी वाले देश में इस कैटेगरी में तेज ग्रोथ की बड़ी संभावना है, अगर लोगों तक इसे सही तरीके से पहुंचाया जाए और अपनाया जाए।" मिलिंद सोमन ने कहा कि, "मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अच्छी सेहत की शुरुआत हमारे रोज के खाने से होती है। टूना लीन प्रोटीन का एक आसान और असरदार सोर्स है। मुझे टेस्टी निबल्स की यह बात पसंद है कि कंपनी इसे लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध और रोजमर्रा के खाने में शामिल करने लायक बना रही है। मैं इस सफर का हिस्सा बनकर खुश हूं, जो लोगों को बेहतर और हेल्दी फूड चुनने के लिए प्रेरित करता है।"

चोरी कर बाहर ले जाई गईं 653 मूर्तियां व वस्तुएं प्रधानमंत्री मोदी के अभियान से वापस आईं : गजेन्द्र सिंह शेखावत

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को कहा कि भारत की प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व की मूर्तियां केवल कला की वस्तुएं नहीं हैं बल्कि हमारी हजारों वर्षों की सभ्यता की निरंतरता का जीवंत प्रतीक हैं। गजेंद्र शेखावत ने संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की बहुमूल्य और खोई हुई सांस्कृतिक विरासत की सफल वापसी के उपलक्ष्य में दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह बात कही।गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा यह भारत की विरासत को पुनः प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत की वापसी को लेकर महत्वपूर्ण उपलब्धियां साझा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे 'विरासत संरक्षण' अभियान के तहत अब तक कुल 666 प्राचीन कलाकृतियाँ भारत वापस लाई जा चुकी हैं। विशेष बात यह है कि इनमें से 653 वस्तुएं अकेले वर्ष 2014 के बाद स्वदेश लौटी हैं। जबकि 1972 से 2014 के बीच केवल 13 पुरावस्तुएं भारत लाई जा सकी थीं। मंत्री ने कहा, "हम अपनी सभ्यता की निरंतरता के इन जीवित प्रतीकों को घर वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत सरकार अपने कूटनीतिक प्रयासों से हर उस धरोहर को वापस लाएगी, जो गलत तरीके से देश से बाहर गई है। अमेरिकी एजेंसियों ने 657 अन्य कलाकृतियां भी जब्त की हैं, जिन्हें भारतीय दूतावास को सौंप दिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जल्द ही इनका परीक्षण और मूल्यांकन कर इन्हें प्रदर्शित करेगा।" शेखावत ने बताया कि कल रात 11 बजे अमेरिका से दो महत्वपूर्ण मूर्तियां भारत पहुँचीं। इनमें चोल काल (12वीं सदी) की सोमस्कंद की मूर्ति और विजयनगर काल (16वीं सदी) की संत सुरिंदर और पारवई की कांस्य प्रतिमा शामिल है। कुल 11 मूर्तियां ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त हुई हैं, जिनमें नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया से 8 और आर्ट गैलरी ऑफ न्यू साउथ वेल्स से 3 मूर्तियां शामिल हैं। इनमें शुंग कालीन टेराकोटा, पाल राजवंश की वराह प्रतिमा और 11वीं सदी की बोधिसत्व प्रतिमा प्रमुख हैं। भारत और अमेरिका के बीच हुए 'सांस्कृतिक संपत्ति विनिमय समझौते' ने इस प्रक्रिया को और गति दी है। मंत्री ने बताया कि अमेरिका के प्रसिद्ध 'स्मिथसोनियन संस्थान' ने तमिलनाडु के मंदिरों से जुड़ी तीन अत्यंत महत्वपूर्ण कांस्य मूर्तियों को भारत को सौंप दिया है। तंजावुर के मंदिर की शिव नटराज की मूर्ति को स्मिथसोनियन संस्थान के अनुरोध पर 3 साल के 'शॉर्ट टर्म लोन' पर अमेरिका में प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। इस मूर्ति को वर्तमान में "दक्षिण एशिया और हिमालय में ज्ञान की कला" प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जा रहा है। इसके अलावा, उन्होंने 127 साल बाद भारत लौटे भगवान बुद्ध के अवशेषों की वापसी को एक बड़ी उपलब्धि बताया। एक सवाल के जबाव में मंत्री ने बताया कि बरामद किए गए पुरावशेषों के लिए लाल किले में एक समर्पित गैलरी बनाई गई है, जिसे और बेहतर बनाने का काम जारी है। टास्क फोर्स से अधिक सरकार के सभी स्टेकहोल्डर्स (प्रवर्तन एजेंसियां, दूतावास, और संस्कृति मंत्रालय) मिलकर इन वस्तुओं को वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट का गूगल-ऐपल को पोर्नोग्राफी बढ़ाने वाले ऐप्स पर सख्त कार्रवाई का निर्देश

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गूगल और ऐपल को निर्देश दिया है कि वो अपने प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर पोर्नोग्राफी और वेश्यावृति को बढ़ावा देने वाले ऐप पर सख्त कार्रवाई करें। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वो पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने गूगल, ऐपल और केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो पोर्नोग्राफी और वेश्यावृति को बढ़ावा देने वाले ऐप को रोकने के लिए कार्रवाई को लेकर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करें। कोर्ट ने कहा कि गूगल और ऐपल अपने प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर ऐसे ऐप अपलोड होते समय ही रोकें। कोर्ट ने कहा कि आईटी रूल्स 2021 के दिशा-निर्देशों के मुताबिक इंटरमीडियरी को ऐसी शिकायतों पर कार्रवाई करने में न केवल मुख्य भूमिका निभानी है, बल्कि उन्हें अपलोड होते समय भी कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गूगल और ऐपल जैसे इंटरमीडियरी को आईटी रुल्स के मुताबिक शिकायतों पर गौर करते हुए उन्हें तुरंत रोकना होगा। याचिका रुबिका थापा ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि गूगल प्ले स्टोर और ऐपल के ऐप स्टोर पर कई ऐसे ऐप उपलब्ध हैं जिनके जरिये पोर्नोग्राफी कंटेंट, अनैतिक तस्करी, वेश्यावृति, हथियारों की तस्करी और संगठित अपराध को बढ़ावा दिया जाता है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील तन्मय मेहता ने कहा कि ये ऐप आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देकर करोड़ों डॉलर की कमाई कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने याचिकाकर्ता की चिंताओं से सहमति जताते हुए कहा कि इन ऐप्स के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाएगी।

दिल्ली सरकार के मंत्री भी पेट्रोल बचाएंगे, कपिल मिश्रा ने किया मेट्रो से सफर

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश पर दिल्ली के सभी मंत्री, अधिकारी एवं कर्मचारी ईंधन बचाने के लिए सभी सम्भव प्रयास करेंगे। यह बात दिल्ली के कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने कही। मिश्रा ने बुधवार को परिवहन के लिए दिल्ली मेट्रो का प्रयोग किया। मेट्रो में सफर के दौरान कपिल मिश्रा ने दिल्ली वासियों से ऊर्जा संरक्षण के विविध तरीकों पर चर्चा की और अन्य लोगों को प्रेरित करने का आग्रह किया। उन्होंने दैनिक जीवन में अपने कार्यालय एवं प्रतिष्ठान जाने के लिए निजी वाहनों का प्रयोग करने वाले दिल्ली वासियों से बस एवं मेट्रो को अपनाने का आग्रह किया। साथ ही घर के नजदीक स्थित बाजारों एवं अन्य जगहों पर जाने के लिए पैदल या साइकिल का प्रयोग करने का आग्रह किया। मिश्रा ने कहा कि वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान का पालन करते हुए ईंधन बचाना एवं ऊर्जा का संरक्षण करना हम सबका राष्ट्रीय कर्तव्य है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी अपने काफिले को आधे से भी कम कर रही हैं। दिल्ली के मंत्री सार्वजनिक परिवहन अपना रहे हैं और अब बहुत आवश्यकता पड़ने पर केवल एक सरकारी गाड़ी का प्रयोग किया जाएगा।

(कैबिनेट) अहमदाबाद-धोलेरा के बीच देश की पहली सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने गुजरात के अहमदाबाद (सरखेज) से धोलेरा के बीच देश की पहली सेमी हाई-स्पीड डबल रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 20,667 करोड़ रुपये है और इसे वर्ष 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बुधवार को गुजरात में अहमदाबाद (सरखेज) से धोलेरा तक सेमी हाईस्पीड डबल रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी। इसकी अनुमानित लागत करीब 20,667 करोड़ रुपये है। इसे वर्ष 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।रेल मंत्रालय की यह परियोजना भारतीय रेल की पहली सेमी हाईस्पीड रेल परियोजना होगी, जिसे स्वदेशी तकनीक के आधार पर विकसित किया जाएगा। परियोजना के तहत करीब 134 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जाएगी।वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बेहद महत्वपूर्ण है। धोलेरा को सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एविएशन कंपोनेंट और सोलर सेल निर्माण के बड़े हाईटेक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। धोलेरा में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाया जा रहा है, जहां से यूरोप के लिए उड़ानें अरब सागर और मध्य-पूर्व के रास्ते संचालित की जा सकेंगी। वैष्णव ने कहा कि परियोजना से अहमदाबाद, धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र (एसआईआर), आगामी धोलेरा एयरपोर्ट और लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएचएमसी) के बीच तेज और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे यात्रियों के यात्रा समय में कमी आएगी। अहमदाबाद को धोलेरा से जोड़ने से यात्रियों का यात्रा समय कम हो जाएगा, जिससे रोज़ाना आना-जाना आरामदायक हो जाएगा और उसी दिन वापस लौटना भी मुमकिन हो पाएगा। यह सेमी-हाई स्पीड रेलवे न सिर्फ़ इन दो शहरों को एक-दूसरे के करीब लाएगा, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों को भी एक-दूसरे के करीब लाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना से सौराष्ट्र क्षेत्र को मुंबई और दक्षिण भारत की मुख्य रेल लाइन से बेहतर संपर्क मिलेगा। परियोजना में मेट्रो नेटवर्क के साथ एकीकरण की भी योजना है।गुजरात के अहमदाबाद ज़िले को कवर करने वाला यह प्रोजेक्ट, भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 134 किलोमीटर तक बढ़ा देगा। यह परियोजना लगभग 284 गांवों और करीब पांच लाख आबादी को बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। रेल मंत्रालय ने कहा कि पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रणाली होने के कारण इस परियोजना से देश के लॉजिस्टिक खर्च में कमी आएगी, तेल आयात में लगभग 0.48 करोड़ लीटर की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में करीब दो करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी, जो लगभग 10 लाख पेड़ लगाने के बराबर होगी।

संक्षिप्त समाचार

चमन सराय में निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे चेयरमैन पति चौधरी मुशीर अली खान

लोकतंत्र की शान , सैय्यद कुमैल ज़ैदी , संभल नगर पालिका परिषद क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। नगर को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से चेयरमैन आसिया मुशीर अली खान के नेतृत्व में नगर पालिका द्वारा युद्ध स्तर पर विकास कार्य कराए जा रहे हैं।

इसी क्रम में आज चमन सराय क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने चेयरमैन पति एवं एआईएमआईएम के वरिष्ठ नेता चौधरी मुशीर अली खान पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा तथा सभी कार्य समय सीमा के भीतर पूरे कराए जाएं। उन्होंने कहा कि संभल शहर अब तेजी से स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है और नगरवासियों को बेहतर सड़कें, साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना नगर पालिका की प्राथमिकता है। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी मणि भूषण तिवारी ने कहा कि नगर पालिका परिषद संभल लगातार विकास कार्यों को गति दे रही है। शहर के विभिन्न वार्डों में सड़क निर्माण, नालियों की मरम्मत, सौंदर्यीकरण और साफ-सफाई के कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं, जिससे संभल की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। नगरवासियों ने भी चेयरमैन आसिया मुशीर अली खान, अधिशासी अधिकारी मणि भूषण तिवारी तथा चेयरमैन पति चौधरी मुशीर अली खान की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि पहली बार संभल में विकास कार्य धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। दिन-रात मेहनत कर नगर को नई पहचान दिलाने का कार्य किया जा रहा है। संभल शहर में हो रहे ऐतिहासिक विकास कार्यों से अब यह साफ नजर आने लगा है कि आने वाले समय में संभल प्रदेश के सुंदर और व्यवस्थित शहरों में अपनी अलग पहचान बनाएगा।

बरेली DM ने उतारी लाल बत्ती की हनकः काफिला छोड़ा, पैदल पहुंचे कलेक्ट्रेट, जिले में लागू किया 'नो व्हीकल डे'

PM-CM की अपील पर बरेली बना रोल मॉडल, हफ्ते में 2 दिन साइकिल से आएंगे अफसर, तहसील दिवस पर ई-बस में भरकर जाएंगे अधिकारी

लोकतंत्र की शान , (बरेली, उत्तर प्रदेश | संदीप चंद्रा) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ईंधन बचाओ और पर्यावरण संरक्षण मुहिम को अब बरेली प्रशासन ने जमीनी रूप देना शुरू कर दिया है। जिले के डीएम अविनाश सिंह ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए न सिर्फ अपने सरकारी काफिले की एस्कॉर्ट गाड़ियां हटाईं, बल्कि पूरे जिले में 'नो व्हीकल डे' लागू कर नई मिसाल पेश कर दी। बुधवार सुबह बरेली में उस समय हर कोई हैरान रह गया जब डीएम अविनाश सिंह अपने सरकारी आवास से कलेक्ट्रेट तक पैदल चलते हुए पहुंचे। उनके साथ सुरक्षा गार्ड, अर्दली और अन्य स्टाफ मौजूद रहा, लेकिन कोई सरकारी गाड़ी या लालबत्ती वाला काफिला नहीं था। डीएम का यह अंदाज देखते ही प्रशासनिक महकमे में चर्चा तेज हो गई। डीएम ने स्पष्ट संदेश दिया कि अब अफसरों की असली जिम्मेदारी केवल दफ्तर चलाना नहीं, बल्कि जनता को संसाधनों की बचत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना भी है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन खुद उदाहरण पेश करेगा तभी आम जनता भी इस मुहिम से जुड़ेगी।

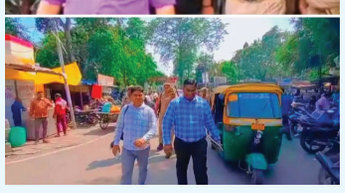

हफ्ते में दो दिन रहेगा 'नो व्हीकल डे'–डीएम के आदेश के बाद अब बरेली में हफ्ते में दो दिन 'नो व्हीकल डे' मनाया जाएगा। इन दिनों जिले के अधिकारी निजी और सरकारी गाड़ियों का उपयोग नहीं करेंगे। सभी अधिकारियों को साइकिल या पैदल कार्यालय पहुंचने के लिए प्रेरित किया गया है।

नीट पेपर लीक पर एआईएमआईएम युवा मोर्चा ने जताया कड़ा रोष, दोबारा परीक्षा कराने की मांग

लोकतंत्र की शान , सैय्यद कुमैल ज़ैदी , सम्भल। बुधवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष नूर मोहम्मद पाशा के नेतृत्व में आयोजित बैठक में नीट पेपर लीक मामले को लेकर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया। बैठक में कहा गया कि इस घटना ने लाखों मेहनती छात्रों और उनके अभिभावकों के सपनों को तोड़ने का काम किया है। जिलाध्यक्ष नूर मोहम्मद पाशा ने कहा कि देश के छात्र दिन-रात मेहनत कर डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन परीक्षा से पहले पेपर लीक होना शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि सरकार और संबंधित विभाग छात्रों को निष्पक्ष परीक्षा कराने में पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि कई अभिभावकों ने अपने बच्चों की पढ़ाई और कोचिंग के लिए आर्थिक परेशानियों के बावजूद हर संभव प्रयास किए, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाओं ने छात्रों का मनोबल तोड़ दिया है। यह केवल परीक्षा का मामला नहीं बल्कि देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। बैठक में मांग की गई कि नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए तथा छात्रों के हित में परीक्षा दोबारा आयोजित कराई जाए। वक्ताओं ने कहा कि केवल फीस वापस करना समाधान नहीं है, बल्कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि छात्रों के भविष्य के साथ इसी तरह खिलवाड़ होता रहा तो युवा सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

निजी नर्सिंग होम में प्रसूता की मौत, परिजनों ने किया हंगामा

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा, हसनपुरः नगर में बायपास मार्ग स्थित एक निजी नर्सिंग होम में उपचार के दौरान एक प्रसूता की मौत का आरोप लगाते हुए परिजनों ने हंगामा काटा और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया, इसके बाद हसनपुर सीएससी प्रभारी ने नर्सिंग होम के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया, प्राप्त जानकारी के अनुसार गजरौला थाना क्षेत्र के निवासी सोनू ने अपनी 29 वर्षीय पत्नी बबीता को प्रसव पीड़ा होने पर सोमवार को उक्त नर्सिंग होम में भर्ती कराया था जहां सिजेरियन ऑपरेशन के जरिए महिला ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया, इसके बाद महिला की स्थिति गंभीर होने पर चिकित्सकों ने मेरठ रेफर कर दिया तथा बुधवार को मेरठ में उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजन शव को लेकर वापस हसनपुर ऊक्त नर्सिंग होम पर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोषीत परिजनों को समझा भुझा कर मामले को शांत कराया, घटना की जानकारी मिलते ही सीएससी प्रभारी डॉक्टर ध्रुबेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंच गए तथा तत्काल कार्रवाई करते हुए नर्सिंग होम के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया, वही कोतवाल राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची थी हालांकि परिजनों ने किसी भी कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया और बिना पोस्टमार्टम के ही शव को घर ले गए जबकि नवजात शिशु पूरी तरह स्वस्थ है, वही परिजनों ने देर श्याम मृतक महिला का अंतिम संस्कार कर दिया।

बरेलीः इज्जतनगर अपहरण कांड का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार

» पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में लगी गोली, चोरी की बाइक और तमंचा बरामद

लोकतंत्र की शान

(बरेली, उत्तर प्रदेश | संदीप चंद्रा) बरेली के थाना इज्जतनगर क्षेत्र में फिरौती के लिए हुए अपहरण कांड में वांछित चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई फायरिंग में एक कांस्टेबल घायल हो गया, जबकि जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। जानकारी के अनुसार मंगलवार देर रात थाना इज्जतनगर पुलिस पीलीभीत रोड स्थित कलापुर पुलिया के पास संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवक पुलिस को देखकर घबरा गए। पुलिस टीम ने जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो दोनों बाइक मोड़कर भागने लगे। संदेह होने पर पुलिस ने पीछा शुरू किया। बताया जा रहा है कि पीछा किए जाने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। अचानक हुई गोलीबारी में कांस्टेबल नीशू तिवारी घायल हो गए। पुलिस टीम ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वह सड़क किनारे गिर पड़ा, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसकी पहचान विमल पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम रिछौला थाना नवाबगंज, बरेली के रूप में हुई। घायल आरोपी को पुलिस सुरक्षा में जिला अस्पताल भेजा गया, वहीं घायल कांस्टेबल का भी उपचार कराया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी थाना इज्जतनगर में दर्ज फिरौती के लिए अपहरण के मामले में वांछित चल रहा था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने अपने साथियों उमाशंकर, आकाश और हरनेश के साथ मिलकर 9 मई को फन सिटी के आगे से एक युवक का अपहरण किया था। इस सनसनीखेज वारदात के बाद से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। मामले में आरोपी उमाशंकर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

चौपाल पुल पुनर्निर्माण आंदोलन की सफलता पर किसान एकता संघ ने बांटी मिठाई

लोकतंत्र की शान

(बरेली, उत्तर प्रदेश | संदीप चंद्रा) बरेलीः–चौपाल पुल के पुनर्निर्माण कार्य शुरू होने पर किसान एकता संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने खुशी जताते हुए कार्यस्थल पर मिष्ठान वितरण किया। संगठन ने इसे लंबे संघर्ष और जनआंदोलन की जीत बताया। बताते चलें कि इस पुल से गुजरने वाले लोगों को लंबे समय से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि सड़क का निर्माण करीब डेढ़ वर्ष पहले ही किया गया था, लेकिन घटिया निर्माण सामग्री और तकनीकी खामियों के चलते पुल कुछ ही महीनों में जर्जर हो गया। ज्वाइंटों के स्थान पर गलत तरीके से सड़क निर्माण होने के कारण पुल पर गहरी नालियां बन गई थीं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को गंभीर दिक्कतें हो रही थीं। स्थानीय लोगों का कहना था कि क्षेत्र में कई जनप्रतिनिधियों के आवास होने के बावजूद इस जनहित के मुद्दे की लंबे समय तक अनदेखी की गई। इसके बाद किसान एकता संघ ने करीब एक वर्ष पूर्व किसान नेता डॉ. रवि नागर के नेतृत्व में पुल के पुनर्निर्माण को लेकर आंदोलन शुरू किया। आंदोलन के दौरान किसान नेताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना अधिकारी उत्कर्ष शुक्ला से कई दौर की वार्ता की। इसके बाद बरेली प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग और किसान नेताओं की संयुक्त समिति गठित की गई, जिसने दिसंबर माह में पुल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद पुल के पुनर्निर्माण की उम्मीद जगी और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इसके लिए करीब 1 करोड़ 45 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया।

बरेली में एसपी को सैल्यूट न करना कांस्टेबल को पड़ा भारी, 15 दिन की विशेष ट्रेनिंग पर भेजा गया

लोकतंत्र की शान

(बरेली, उत्तर प्रदेश | संदीप चंद्रा) उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में अनुशासन और प्रोटोकॉल को लेकर एक बार फिर सख्ती देखने को मिली है। बरेली जिले के आंवला थाना क्षेत्र में तैनात एक कांस्टेबल को वरिष्ठ अधिकारी को सैल्यूट न करना महंगा पड़ गया। मामले में एसपी साउथ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल को 15 दिन की "स्पेशल सैल्यूट ट्रेनिंग" पर भेज दिया है। यह मामला पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के अनुसार, एसपी साउथ अंशिका वर्मा आंवला थाने के निरीक्षण पर पहुंची थीं। निरीक्षण के दौरान थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें नियमानुसार सैल्यूट किया गया, लेकिन कांस्टेबल परमसिंह ने कथित तौर पर उन्हें सैल्यूट नहीं किया। इस पर एसपी साउथ ने नाराजगी जताई और इसे पुलिस अनुशासन एवं विभागीय मर्यादा के विपरीत माना। सूत्रों के मुताबिक, एसपी साउथ ने मौके पर ही कांस्टेबल से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद विभागीय अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से उसे 15 दिन की विशेष प्रशिक्षण प्रक्रिया में भेजने का आदेश जारी किया गया। इस ट्रेनिंग में उसे पुलिस प्रोटोकॉल, वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति व्यवहार और सैल्यूट की प्रक्रिया का अभ्यास कराया जाएगा। पुलिस विभाग में सैल्यूट केवल औपचारिकता नहीं बल्कि अनुशासन, सम्मान और संगठनात्मक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि पुलिस बल में अनुशासन सर्वोपरि होता है और छोटी लापरवाही भी गलत संदेश दे सकती है। यही कारण है कि विभाग इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेता है। हालांकि, इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर बहस भी छिड़ गई है। कुछ लोग इसे अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे अत्यधिक कठोर कार्रवाई मान रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि पुलिसकर्मियों पर पहले से ही अत्यधिक कार्यभार रहता है और मानवीय भूल को ट्रेनिंग के जरिए सुधारना बेहतर विकल्प हो सकता है।

सपा जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी के पिता एवं पूर्व प्रधान अकबर हुसैन अंसारी का इंतकाल, ग्राम बराही में सुपुर्द-ए-खाक

लोकतंत्र की शान

संभल/सिरसी संभल समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी के पिता एवं ग्राम बराही के पूर्व प्रधान अकबर हुसैन अंसारी का इंतकाल हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मरहूम को उनके पैतृक गांव बराही में सुपुर्द-ए-खाक किया गया, जहां बड़ी तादाद में लोगों ने पहुंचकर नम आंखों से अंतिम विदाई दी। जनाज़े में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, ग्राम प्रधान, सामाजिक एवं राजनीतिक हस्तियों सहित दूर-दराज क्षेत्रों से आए लोगों ने भी शिरकत की। इस दौरान उपस्थित लोगों ने मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की तथा शोक संतप्त परिवार को सब्र बख्शने की दुआ मांगी। वक्ताओं ने कहा कि अकबर हुसैन अंसारी एक सादगी पसंद, मिलनसार और जनप्रिय व्यक्तित्व के धनी थे। पूर्व प्रधान रहते हुए उन्होंने गांव के विकास और सामाजिक भाईचारे के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसकी वजह से क्षेत्र में उनका विशेष सम्मान था। जनाज़े में शामिल लोगों ने असगर अली अंसारी को सांत्वना देते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा समाजवादी परिवार उनके साथ खड़ा है। वहीं ग्राम बराही में देर शाम तक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा रहा। दफन में राज्यसभा सांसद जावेद अली खान संभल लोकसभा सांसद जियाउल रहमान वर्क बिलारी विधायक फ़हीम इरफान सम्भल विधायक नवाब इकबाल महमूद संभल मार्केटिंग के पूर्व चेयरमैन चौधरी सैयद मोहम्मद फैजान अली नक़वी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व समाज सेवक व क्षेत्र के सम्मानित नागरिक दफन में शरीक हुए

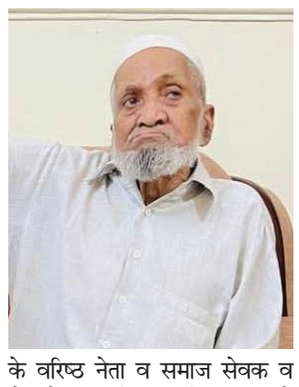

नाथ कॉरिडोर से बदलेगी बरेली की धार्मिक तस्वीर

» 60 करोड़ की परियोजनाओं से सजेगा प्राचीन नाथ धाम, आध्यात्मिक पर्यटन को मिलेगा नया विस्तार

लोकतंत्र की शान

(बरेली, उत्तर प्रदेश | संदीप चंद्रा) उत्तर प्रदेश सरकार अब बरेली की प्राचीन नाथ परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के निर्देशन में शुरू की गई "नाथ कॉरिडोर परियोजना" के तहत बरेली के प्रमुख धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थलों का व्यापक विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। लगभग 60 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य न केवल धार्मिक विरासत को संरक्षित करना है, बल्कि बरेली को देश के बड़े "स्पिरिचुअल टूरिज्म हब" के रूप में स्थापित करना भी है। प्रदेश सरकार "विकास भी, विरासत भी" की थीम पर कार्य करते हुए भगवान शिव और नाथ परंपरा से जुड़े प्राचीन मंदिरों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ रही है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री Jaiveer Singh के अनुसार सरकार नाथ संप्रदाय की ऐतिहासिक धरोहरों को एक सूत्र में पिरोकर धार्मिक पर्यटन को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका कहना है कि इन स्थलों की आध्यात्मिक गरिमा और पौराणिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। नाथ कॉरिडोर योजना के अंतर्गत बरेली के कई प्रमुख मंदिरों का सौंदर्यीकरण, पुनर्विकास और आधारभूत ढांचे का विस्तार किया जा रहा है। सदर कैंट स्थित प्रसिद्ध श्री दोपेश्वर नाथ मंदिर के विकास पर लगभग 7 करोड़ 74 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं। वहीं जोगी नवादा स्थित बनखंडीनाथ मंदिर पर 5 करोड़ 82 लाख रुपये की परियोजना संचालित है। त्रिवेटीनाथ मंदिर के विकास पर 6 करोड़ 55 लाख रुपये तथा तपेश्वर नाथ मंदिर पर 8 करोड़ 36 लाख रुपये की लागत निर्धारित की गई है। करीब 930 वर्ष पुराने ऐतिहासिक अलकनाथ मंदिर को भी इस परियोजना में विशेष महत्व दिया गया है। मंदिर के विकास पर लगभग 11 करोड़ 67 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। यहां भव्य मुख्य द्वार, वैदिक लाइब्रेरी, श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक प्रतीक्षालय, पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। सरकार का मानना है कि अलकनाथ मंदिर नाथ परंपरा की पहचान के रूप में देशभर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा। इसके अतिरिक्त पीलीभीत बाईपास रोड स्थित पशुपतिनाथ मंदिर, तुलसी मठ तथा मणिनाथ मंदिर को भी नाथ कॉरिडोर से जोड़ा गया है। सावन के दौरान लाखों की संख्या में आने वाले कांवड़ यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगभग 4 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से यात्री शेड, विश्राम गृह, परिक्रमा मार्ग, एलईडी लाइटिंग, टॉयलेट ब्लॉक तथा सौंदर्यीकरण के कार्य कराए जा रहे हैं। शहर के 19 प्रमुख स्थलों पर आकर्षक "फोकस वॉल" भी बनाई जाएंगी, जो धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाएंगी। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में बरेली में एक करोड़ से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचे थे। माना जा रहा है कि नाथ कॉरिडोर परियोजना के पूर्ण होने के बाद यह संख्या और तेजी से बढ़ेगी। इससे स्थानीय व्यापार, होटल उद्योग, परिवहन और रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे।

पाकिस्तान से जुड़े लिंक के शक में रामपुर का युवक STF ने किया गिरफ्तार, लखनऊ ले जाकर पूछताछ

लोकतंत्र की शान, मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा

रामपुर। उत्तर प्रदेश/जनपद रामपुर के थाना मझरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ताशका निवासी एक युवक को पाकिस्तान से कथित संपर्क होने के संदेह में एसटीएफ लखनऊ टीम ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक की पहचान मोहम्मद ग्यास पाशा (उम्र करीब 21 वर्ष) पुत्र तौफीक के रूप में बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार एसटीएफ टीम युवक को हिरासत में लेकर लखनऊ रवाना हो गई, जहां उससे गहन पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि युवक के मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट व अन्य दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसका संपर्क किन लोगों से था और वह किन गतिविधियों में शामिल था। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुटी हैं। वहीं स्थानीय स्तर पर भी घटना को लेकर चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। फिलहाल एसटीएफ की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। (खबर लिखे जाने तक जांच जारी थी।)

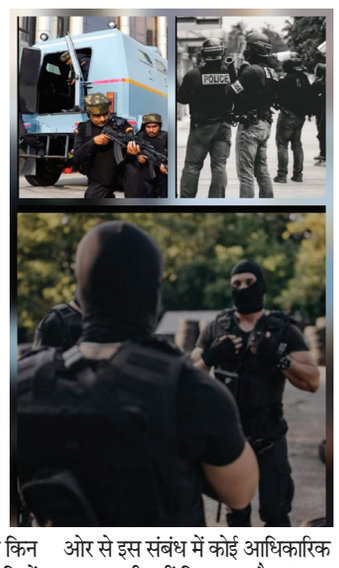

अपर्णा यादव के घर पहुंचे मुख्यमंत्री प्रतीक के निधन पर जताया शोक

पार्थिव शरीर को दी पुष्पांजलि, परिजनों को ढांढस भी बंधाया

लोकतंत्र की शान

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के घर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उनके पति प्रतीक यादव के निधन पर शोक प्रकट करते हुए पार्थिव शरीर को पुष्पांजलि दी। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पुत्र एवं अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का बुधवार सुबह आकस्मिक निधन हो गया था। मुख्यमंत्री ने अपर्णा यादव, उनके बच्चों व अन्य परिजनों को ढांढस भी बंधाया। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। सीएम ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं भी जताईं।

क्षेत्राधिकारी बिलासपुर द्वारा थाना खजुरिया का किया गया त्रैमासिक निरीक्षण

लोकतंत्र की शान, मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा

रामपुर/ उत्तर प्रदेश/ पुलिस अधीक्षक, सोमेंद्र मीणा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी बिलासपुर द्वारा थाना खजुरिया का त्रैमासिक निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय पर बने अपराध रजिस्टर, त्यौहार रजिस्टर, आईजीआरएस रजिस्टर, ऑर्डर बुक, जनशिकायती रजिस्टर, मालमुकदमाती रजिस्टर, मिशन शक्ति रजिस्टर, फ्लाई शीट, रजिस्टर नं0-8 व अन्य अभिलेखों तथा थाना परिसर में बने थाना कार्यालय, जी0डी0 कार्यालय, हवालात, मालखाना, मिशन शक्ति केन्द्र, साइबर सैल, सीसीटीएनएस कक्ष, भोजनालय, आगन्तुक कक्ष, शौचालय व विवेचना कक्ष आदि का मुआयना कर साफ-सफाई को चैक कर संबंधित को निम्न आदेश-निर्देश दिये गये मिशन शक्ति के अन्तर्गत चलाये जा रहे विभिन्न अभियान, महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण हेतु स्थापित महिला हेल्पडेस्क के प्रभावी क्रियान्वयन व महिला बीट प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की कार्यवाही कराये जाने व महिला बीट कर्मियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओ को नियमित रुप से जागरुक किया जायें । मिशन शक्ति केन्द्र का निरीक्षण कर अभिलेखो को चेक कर आवेदिका/आने वाली पीड़िता का नाम, पता, मो0नं0 एवं समस्या का स्पष्ट उल्लेख करने तथा समस्या के निराकरण हेतु की गयी कार्यवाही एवं समस्या के निदान के विवरण का स्पष्ट उल्लेख करने एवं लम्बित महिला सम्बन्धी अपराधों में प्रभावी रुप से कार्यवाही करते हुए उनका शीघ्र निस्तारण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया । थाना स्तर पर प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों को गम्भीरतापूर्वक, गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण कराया जाये । जनसुनवाई पोर्टल (आईजीआरएस) पर लम्बित प्रार्थना पत्रों को समयावधि में निस्तारित किया जाये। अपराध रजिस्टर का अवलोकन कर लम्बित विवेचनाओं के शीघ्र गुण-दोष के आधार पर त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाये । भूमि-विवाद सम्बन्धित प्रकरणों में राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण किया जाये ।विभिन्न ऑनलाइन पॉर्टल पर की जाने वाली फीडिंग को चैक कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।थाना पर आगन्तुको के लिए उचित व्यवस्था एवं समस्याओ के त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया ।थाना परिसर की साफ-सफाई तथा अभिलेखों के रखरखाव एवं उनमें अंकित की जाने वाली पृवष्टियों व थाने पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरो को सुचारू रूप से क्रियाशील रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।

संक्षिप्त समाचार

बिहार के 3 मंत्री एक ही गाड़ी में वैशाली पहुंचे, बोले- आगे बड़ी चुनौती, पहले से तैयारी करनी होगी

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। बिहार में तीन मंत्रियों ने एक ही गाड़ी में वैशाली के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। हालांकि उनके पीछे कार्यकर्ताओं और सिक्योरिटी मिलाकर 8 गाड़ियों का काफिला नजर आया। मंत्रियों ने कहा कि उन्होंने यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचाओ अपील के बाद उठाया है। उनके एक साथ जाने से दो मंत्रियों पर आने वाली गाड़ियों का खर्च बचेगा। वैशाली के महुआ में आयोजित एक कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के मंत्री संजय सिंह, गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री संजय पासवान और अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री लखेंद्र पासवान शामिल हुए। तीनों मंत्रियों ने अपने अलग-अलग काफिले के बजाय एक ही सरकारी गाड़ी में यात्रा की। मंत्रियों ने अपने विभागीय प्रोटोकॉल से ऊपर उठकर कार पूलिंग के माध्यम से जनता के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इसका लक्ष्य सरकारी खर्च में कटौती करना और आम जनता को भी ईंधन बचाने के लिए प्रेरित करना है। इस संबंध में बिहार के मंत्री संजय सिंह ने कहा, "प्रधानमंत्री ने देशहित में ईंधन के संयमपूर्ण उपयोग की जो अपील की है, उसे लागू करना हम सभी का कर्तव्य है। आज हम तीनों मंत्रियों ने एक ही गाड़ी से महुआ जाने का निर्णय लिया है ताकि देश के विदेशी मुद्रा भंडार और ऊर्जा संसाधनों की बचत में हम अपना छोटा सा योगदान दे सकें।" उन्होंने आगे कहा कि बिहार सरकार प्रधानमंत्री के ईंधन संरक्षण मिशन के साथ मजबूती से खड़ी है। मंत्रियों की इस पहल को सराहा जा रहा है, और उम्मीद है कि यह संदेश आम नागरिकों को भी ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक करेगा।

वैशाली में ओवरलोड ट्रैक्टर ने व्यक्ति को रौंदा, मौत:एक्सीडेंट के बाद नाराज लोगों ने रोड जाम किया

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र में एक ओवरलोड गिट्टी लदे ट्रैक्टर ने एक व्यक्ति को कुचल दिया। इस हादसे में व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने हाजीपुर-लालगंज मुख्य मार्ग को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। यह घटना लालगंज थाना क्षेत्र के पोझिया चौक पर हुई। जानकारी के अनुसार, तेज रफ्तार में जा रहे गिट्टी लदे ओवरलोड ट्रैक्टर ने सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति को कुचल दिया। मृतक की पहचान अकबरपुर गांव निवासी अशोक राय के रूप में हुई है। हादसे के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और उन्होंने हाजीपुर-लालगंज मुख्य मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया। सड़क जाम होने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे यातायात बाधित हो गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस मार्ग पर ओवरलोड वाहनों का संचालन लगातार जारी रहता है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती। लोगों ने यह भी कहा कि यदि समय रहते इन वाहनों पर रोक लगाई जाती, तो इस दुर्घटना को टाला जा सकता था। घटना की सूचना मिलते ही लालगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराने का प्रयास किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस हालात को सामान्य करने की कोशिश कर रही है।

बच्चे की गंगा में डूबने से मौत, भाई की शादी से पहले गई जान, दोस्तों के साथ नहाने गया था

लोकतंत्र की शान : हाजीपुर। वैशाली जिले में एक दुखद घटना सामने आई है। पहलेजा थाना क्षेत्र के नौ डिहा सैदपुर में गंगा स्नान के दौरान 17 वर्षीय किशोर विनय कुमार की डूबने से मौत हो गई। वह अपने ममेरे भाई की शादी में शामिल होने नानी घर आया था। जानकारी के अनुसार, विनय अपने दोस्तों के साथ गंगा में स्नान करने गया था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। वहां मौजूद लोगों ने उसे तुरंत बाहर निकाला और सोनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने जांच के बाद विनय को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र के कोयला मोहन गांव निवासी रामानंद राय के पुत्र विनय कुमार के रूप में हुई है। विनय 8 मई को अपनी नानी के घर आया था ताकि वह शादी समारोह में शामिल हो सके। इस घटना से परिवार में खुशी का माहौल मातम में बदल गया है। सोनपुर थाने की पुलिस ने आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया गया है कि विनय अपने माता-पिता और भाई-बहन में सबसे छोटा था। उसके पिता मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करते हैं। विनय अपनी मां और भाई के साथ नानी घर आया था और मेहंदी की रस्म से पहले गंगा स्नान के लिए घाट पर पहुंचा था।

रेलवे 15 मई से लीची पार्सल बुकिंग शुरू करेगा देश के अलग-अलग राज्यों में ट्रेन से भेजा जाएगा

लोकतंत्र की शान : मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की मशहूर शाही लीची अब रेलवे से देश के बड़े शहरों तक पहुंचेगी। रेलवे ने 15 मई से लीची पार्सल बुकिंग शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है। इस बार किसानों और कारोबारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि लीची तेजी से और ताजा हालत में मुंबई समेत अन्य शहरों तक पहुंच सके। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जंक्शन परिसर में धर्मशाला चौक के पास इंजीनियरिंग विभाग की नई बिल्डिंग के सामने बुकिंग कार्यालय बनाया गया है। यहीं पर किसान और व्यापारी अपनी लीची का वजन कराकर बुकिंग करा सकेंगे। इसके बाद सामने स्थित सैलून साइडिंग में खड़ी वीपी यानी वैन पार्सल में लीची की लोडिंग की जाएगी। रेलवे की योजना के मुताबिक पवन एक्सप्रेस के मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचने पर पार्सल वैन को ट्रेन से जोड़ा जाएगा, जिसके जरिए लीची की खेप मुंबई भेजी जाएगी। हर साल बड़ी मात्रा में मुजफ्फरपुर की शाही लीची महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में जाती है और इस बार भी रिकॉर्ड खेप भेजे जाने की संभावना जताई जा रही है। रेलवे ने इस बार भुगतान व्यवस्था को भी आसान बनाया है। पार्सल इंचार्ज भरत कुमार ने बताया कि कारोबारियों को भुगतान में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। नगद के साथ-साथ डिजिटल पेमेंट की भी सुविधा दी गई है। कारोबारी क्यूआर कोड स्कैन कर सीधे रेलवे के खाते में भुगतान कर सकेंगे। रेलवे की इस पहल से लीची कारोबारियों और किसानों में उत्साह है। कारोबारियों का कहना है कि समय पर बुकिंग और तेज पार्सल सेवा मिलने से मुजफ्फरपुर की शाही लीची देशभर के बाजारों तक ताजा और बेहतर गुणवत्ता में पहुंच सकेगी।

दो बहनों की हत्या, खेलने के दौरान 2 दिन पहले गायब हुई थीं, शरीर पर चोट के निशान

लोकतंत्र की शान : मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में बुधवार की सुबह 2 दिन से लापता 2 बहनों की लाश मिली है। दोनों की बॉडी मकसूदपुर ईंट भट्ठे के पास मिली। पुलिस की माने तो लाशें सड़ने लगी थीं। आशंका जताई जा रही है कि 2 दिन पहले ही ये हत्याएं की गई हैं। बच्चियों के सिर, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट के निशान हैं। मृत बच्चियों की पहचान मौसम कुमारी (12) और रूचि कुमारी (7) के रूप में हुई है। परिजन के अनुसार 2 दिन पहले दोनों चचेरी बहनें घर के बाहर खेल रही थीं। गांव में शादी थी, दोनों वहां बार-बार आना-जाना कर रही थीं। देर शाम तक वो घर नहीं लौटीं। जिसके बाद खोजबीन शुरू की गई। दोनों कहीं नहीं मिलीं। इसके बाद पुलिस को सूचना दी। घटना मीनापुर के रामपुरहरी थाना क्षेत्र की है। मृत बच्ची मौसम की मां रितु देवी ने बताया कि, 'मेरी बेटी 5वीं में पढ़ती थी। गांव में किसी से हमारा विवाद नहीं है। बच्ची घर के दरवाजे पर खेल रही थी। गांव में शादी भी थी। मेरी बेटी वहां भी आ-जा रही थी। इसी दौरान उसे कोई उठा ले गया और मारकर ईंट भट्ठे के पास फेंक दिया। मेरी बेटी को बेरहमी से पीट-पीटकर मारा गया है। बच्ची के दांत तक तोड़े गए हैं। उसके शरीर चोट के निशान हैं। लापता होने के बाद पुलिस को सूचना दी थी। हमें जान के बदला जान चाहिए। जिसने भी ये किया है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए।' पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।

2 शार्प शूटर्स का एनकाउंटर, विदेशी साव-पप्पू राय को मारी गोली

लोकतंत्र की शान , पटना

- एसटीएफ बोली- बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे

बिहार पुलिस एक्शन में है। पटना में देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें 2 शार्प शूटर विदेशी साव और पप्पू राय को पुलिस ने दौड़ाकर गोली मारी है। दोनों के पैर में गोली लगी है।

इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबकि एक बदमाश दीपक कुमार को अरेस्ट किया है। बीते दिनों पटना के गौरीचक थाना इलाके में हुए अंजनी सिंह हत्याकांड में तीनों अपराधी शामिल थे। तीनों ने शूटर के तौर पर काम किया था। पुलिस की माने तो तीनों किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए बिहटा इलाके में पहुंचे थे। विदेशी साव और पप्पू राय पर हत्या के कई केस दर्ज हैं। पुलिस ने घटनास्थल से कई हथियार भी बरामद किए हैं। महिला रिपोर्टर ने 2 दिन पहले डॉक्टर बनकर ऑपरेशन कॉन्ट्रैक्ट किलर में शूटर से पति के मर्डर की पूरी डील की थी। इसके बाद पुलिस ने शूटर्स पर ये बड़ा एक्शन लिया है।

पुलिस बोली- पहले अपराधियों ने टीम पर फायरिंग की: पुलिस ने बताया कि STF को जानकारी मिली थी कि बिहटा क्षेत्र में 3 अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। पुलिस ने दोनों का लोकेशन ट्रैक करना शुरू किया। कुख्यात अपराधियों का लोकेशन बिहटा के आनंदपुर गांव के बांध के पास मिला। पुलिस ने दोनों बदमाशों को घेर लिया। पुलिस के मुताबिक खुद को घिरता देख दोनों अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। दोनों अपराधियों को पैर में गोली लगी। पुलिस ने दोनों को सरेंडर करने को कहा। दोनों हाथ उठाकर आगे बढ़े। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस दोनों को बिहटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाई। इसक बाद बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स रेफर किया गया है।

ओसामा शहाब की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

लोकतंत्र की शान , पटना

- सीवान पुलिस गिरफ्तार करने पटना पहुंची थी, डॉक्टर दंपती को धमकी देने का आरोप

पटना हाईकोर्ट ने सीवान कोर्ट के फैसले को पलटते हुए RJD विधायक ओसामा शहाब की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के फैसले से ठीक पहले पटना में उनके आवास पर गिरफ्तार करने सीवान पुलिस पहुंच चुकी थी। मामला सीवान के महादेवा में एक जमीनी विवाद से जुड़ा है, जिसमें एक डॉक्टर दंपति ने FIR दर्ज कराई थी। ओसामा शहाब सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा से विधायक हैं और बाहुबली पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र हैं।

ओसामा को गिरफ्तार करने पटना पहुंची थी सीवान पुलिस: दरअसल, ओसामा शहाब की गिरफ्तारी के लिए सीवान पुलिस बुधवार को पटना पहुंची थी। सीवान SP अजय कुमार सिंह ने पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित MLA फ्लैट में छापेमारी की। हालांकि, ओसामा अपने सरकारी आवास पर मौजूद नहीं हैं। आवास के अंदर RJD विधायक के दो-तीन करीबी मौजूद थे, जिनसे पूछताछ की गई। उनलोगों ने पुलिस को बताया कि मामले में कोर्ट से स्टे मिला हुआ है। इसके बाद पुलिस ने स्टे से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। छापेमारी को लेकर भास्कर ने जब सीवान एसपी अजय सिंह से बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने मामले पर सीधे तौर पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।

निशांत आज पहली बार जनसुनवाई में होंगे शामिल

लोकतंत्र की शान , पटना

- पटना के जदयू कार्यालय पहुंचे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे, मंत्री रत्नेश सादा और दामोदर रावत भी मौजूद

जनता दल यूनाइटेड की जन सुनवाई में आज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार शामिल होंगे। वे पटना स्थित जेडीयू कार्यालय पहुंच गए हैं। जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत निशांत आज जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान भी निकालेंगे। यह पहला मौका है जब निशांत आम जनता के बीच बैठकर जनसुनवाई जैसे कार्यक्रम में शामिल होंगे। जनसुनवाई कार्यक्रम में निशांत कुमार के साथ मंत्री रत्नेश सादा और दामोदर रावत भी मौजूद रहेंगे।

स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद बढ़ी सक्रियता: स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद निशांत कुमार की राजनीतिक और प्रशासनिक सक्रियता लगातार बढ़ी है। इससे पहले निशांत अब तक सिर्फ कार्यकर्ताओं से मिलते रहे हैं। बिहार की यात्रा शुरू करने के बाद उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया था। अब वे बतौर स्वास्थ्य मंत्री विभाग के कामकाज देख रहे हैं, वहीं आज आम जनों के समस्याओं को सुनकर उसका समाधान निकालेंगे।

माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए सरकार जनता से सीधा संवाद मजबूत करने की कोशिश कर रही है।

पटना में आज शाम बजेगा सायरन, 15 मिनट रहेगा ब्लैकआउट, जिला प्रशासन का मॉकड्रिल

लोकतंत्र की शान , पटना

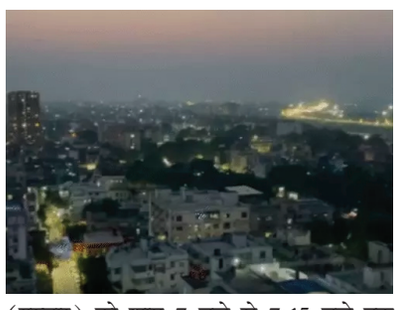

- हवाई हमले जैसे हालात से निपटने का होगा अभ्यास, डीएम बोले- घबराएं नहीं

राजधानी पटना में बुधवार शाम लोगों को अलग माहौल देखने को मिलेगा। शहर के कई इलाकों में अचानक सायरन बजेगा, लाइटें बंद होंगी और प्रशासनिक टीमें एक्टिव नजर आएंगी। हालांकि, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने साफ किया है कि यह किसी वास्तविक खतरे की स्थिति नहीं बल्कि, सिविल डिफेंस का बड़ा मॉकड्रिल और ब्लैकआउट अभ्यास होगा। जिला प्रशासन के अनुसार, यह अभ्यास आपदा और हवाई हमला जैसी आपात स्थिति में तैयारियों को परखने के लिए किया जा रहा है। पूरे शहरी इलाके में एक साथ यह अभ्यास कर प्रशासन की तैयारियों को परखा जाएगा। मुख्य मॉकड्रिल से पहले बुधवार को पटना समाहरणालय में टेबल-टॉप एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी। इसमें हवाई हमले जैसी स्थिति में विभिन्न विभागों की भूमिका और त्वरित प्रतिक्रिया का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। अधिकारियों को आपसी समन्वय और त्वरित कार्रवाई को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

शाम 7 बजे से 15 मिनट तक रहेगा ब्लैकआउट: जिला प्रशासन के अनुसार 14 मई (गुरुवार) को शाम 7 बजे से 7:15 बजे तक पटना के शहरी क्षेत्रों में सिविल डिफेंस ब्लैकआउट किया जाएगा। जैसे ही सायरन बजेगा, लोगों को अपने घरों, दुकानों, कार्यालयों और प्रतिष्ठानों की लाइट बंद करनी होगी। प्रशासन ने लोगों से सहयोग करने और इसे गंभीरता से लेने की अपील की है। यह मॉकड्रिल सिर्फ पटना नगर निगम क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। इसके अलावा दानापुर निजामत, खगौल और फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्रों में भी ब्लैकआउट और हवाई हमलों को लेकर मॉक अभ्यास किया जाएगा।

मॉकड्रिल के दौरान लोगों को कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी होंगी: जिलाधिकारी ने कहा है कि, 'लोग पैनिक बिल्कुल न हों। यह केवल एक पूर्व निर्धारित अभ्यास है, ताकि किसी वास्तविक आपदा की स्थिति में प्रशासन और नागरिक दोनों तैयार रहें।' 14 मई को तय समय पर करीब 2 मिनट तक सिविल डिफेंस का सायरन बजेगा। इसे हवाई हमले की चेतावनी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। सायरन बजते ही ब्लैकआउट लागू हो जाएगा और विभिन्न एजेंसियां राहत और बचाव कार्यों का अभ्यास शुरू करेंगी। मॉकड्रिल के लिए पटना में कई महत्वपूर्ण जगहों को सिमुलेशन साइट बनाया गया है। इनमें पटना समाहरणालय, बिस्कोमान भवन, बांकीपुर बस स्टैंड, आईजीआईएमएस शामिल हैं। यहां हवाई हमले जैसी काल्पनिक स्थिति तैयार कर राहत और बचाव कार्यों का अभ्यास किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पूरी गतिविधियों की निगरानी करेंगे।

पटना में स्कूल जा रहे शिक्षक को गोली मारी

लूटपाट के दौरान हुई घटना, मोबाइल छीनने का किया विरोध; निजी अस्पताल में भर्ती

लोकतंत्र की शान , पटना

पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को गोली मारकर घायल कर दिया गया। यह घटना नेशनल हाईवे स्थित नरल पेट्रोल पंप के पास मिश्रा वैली स्कूल के समीप हुई। घायल शिक्षक की पहचान 48 वर्षीय शंभू कुमार के रूप में हुई है, जो चंडी के एक सरकारी विद्यालय में कार्यरत हैं। उन्हें इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है।

स्कूल जाने के दौरान बदमाशों ने घेरा: जानकारी के अनुसार, शंभू कुमार बुधवार सुबह अपने घर से विद्यालय जाने के लिए निकले थे। वह नेशनल हाईवे पर पैदल वाहन का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार दो अपराधी उनके पास पहुंचे और उनसे बैग तथा मोबाइल लूटने का प्रयास करने लगे।

विरोध करने पर मारी गोली: जब शिक्षक शंभू कुमार ने इसका विरोध किया, तो अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। गोली उनके गले के नीचे लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। घटना के बाद अपराधी उनका मोबाइल और बैग लूटकर मौके से फरार हो गए।

गोली की आवाज सुन जुटे लोग: गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और घायल शिक्षक को इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम में पहुंचाया।

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस: घटना की सूचना मिलते ही अगमकुआं थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। अगमकुआं थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला लूटपाट का प्रतीत होता है। अपराधियों ने शिक्षक से बैग और मोबाइल छीनने का प्रयास किया था, और विरोध करने पर उन्हें गोली मार दी गई। पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। उनका कहना है कि सुबह के समय भी नेशनल हाईवे पर अपराधी बेखौफ होकर ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।

किसी से कोई विवाद नहीं था- पत्नी: घायल शिक्षक की पत्नी अंजनी कुमारी ने बताया कि उनके पति शंभू कुमार का किसी से कोई विवाद नहीं था। प्रत्येक दिन की तरह वह बुधवार की सुबह भी अपना बैग लेकर स्कूल के लिए निकले थे। पुलिस द्वारा उन्हें सूचना दी गई कि उनके पति को गोली लग गई है। भाग कर वे अस्पताल पहुंचे।

बाढ़ में 17 साल पुराना पुल ढहा, गड्ढे में गिरकर 5 युवक दबे

लोकतंत्र की शान , पटना

- ग्रामीणों ने बांस-लकड़ी के सहारे निकाला बाहर, तीन की हालत गंभीर

पटना के बाढ़ अनुमंडल के सकसोहरा थाना क्षेत्र स्थित दल्लोचक गांव में 17 साल पुराना ग्रामीण पुल अचानक ढह गया। हादसे के समय पुल पर बैठे पांच युवक नीचे गड्ढे में गिरकर घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने पर डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है।

अचानक भरभराकर गिरा पुल: ग्रामीणों के मुताबिक, घटना सुबह करीब 10:30 बजे की है। पुल पर पांच से सात युवक बैठकर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान अचानक पुल भरभराकर गिर पड़ा। पुल टूटते ही वहां बैठे युवक नीचे जा गिरे और मलबे में फंस गए।

ग्रामीणों ने बचाई युवकों की जान: हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और बांस व लकड़ी के सहारे फंसे युवकों को बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया।

क्लास में सोता रहा टीचर, मैदान में खेलते दिखे बच्चे

लोकतंत्र की शान , पटना

पटना के बाढ़ अनुमंडल के इब्राहिमपुर नयाटोला प्राथमिक स्कूल में शिक्षकों की लापरवाही का मामला सामने आया है। स्कूल प्रभारी का क्लासरूम में सोते हुए और बच्चों का मैदान में क्रिकेट खेलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार, स्कूल के अन्य शिक्षक इन दिनों जनगणना कार्य में लगे हुए हैं। वे सुबह ड्यूटी पर निकल जाते हैं, जिसके बाद स्कूल की जिम्मेदारी प्रभारी शिक्षक पर रहती है। आरोप है कि प्रभारी शिक्षक क्लास में ही सो जाते हैं और बच्चे क्लास छोड़कर मैदान में क्रिकेट खेलने चले जाते हैं।

ग्रामीणों ने बनाया वीडियो: ग्रामीणों का कहना है कि वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन प्रभारी शिक्षक बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। स्थानीय लोगों ने बताया कि इसको लेकर कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने प्रभारी को सबक सिखाने के लिए सोते हुए उनका वीडियो बना लिया। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी प्रभारी शिक्षक का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे स्कूल परिसर में एक महिला को छड़ी से पीटते नजर आए थे। उस मामले में बीईओ अमित कुमार ने कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को पत्र लिखा था। बीईओ अमित कुमार ने कहा कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल समय में शिक्षक के सोते हुए वीडियो सामने आने के मामले को गंभीरता से लिया गया है और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

डीजल बसों की जगह अब बिहार में इलेक्ट्रिक बसें

लोकतंत्र की शान , पटना

- बिहार में शुरू होगा 400 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन, जुलाई महीने से पहले सड़कों पर उतरेंगी 200 ई-बसें

बिहार में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार की पीएम ई-बस सेवा योजना फेज-II के तहत अगले माह बिहार को 200 अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इन बसों के परिचालन से राज्य की परिवहन व्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी, वहीं यात्रियों को भी आधुनिक और सुरक्षित सफर का अनुभव मिलेगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) की ओर से इस योजना को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी गई है। निगम द्वारा इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति, संचालन और रखरखाव के लिए ग्रीनसेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड को लेटर ऑफ अवार्ड जारी कर दिया गया है। इस एजेंसी का चयन भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया है।

जून के अंत तक शुरू हो सकता है परिचालन: परिवहन सचिव राज कुमार ने बताया कि योजना के पहले चरण में जून माह के प्रथम सप्ताह तक 200 इलेक्ट्रिक बसें बिहार पहुंच जाएंगी। इसके बाद जून के अंतिम सप्ताह तक इन बसों का परिचालन शुरू करने का लक्ष्य तय किया गया है। पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत बिहार में कुल 400 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन किया जाएगा।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक अतुल कुमार वर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। ग्रीनसेल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 9 मीटर श्रेणी की 200 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति की जाएगी। यही कंपनी बसों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी भी संभालेगी। पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत इन बसों का संचालन ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (GCC) मॉडल पर किया जाएगा। इस मॉडल में बसों के संचालन, रखरखाव और तकनीकी सेवाओं की जिम्मेदारी निजी एजेंसी की होगी, जबकि सरकार यात्रियों को बेहतर सेवा सुनिश्चित करेगी।

इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए जरूरी इलेक्ट्रिक और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन, आधुनिक बस डिपो और अन्य तकनीकी सुविधाओं पर तेजी से काम चल रहा है ताकि बसों का परिचालन बिना किसी बाधा के किया जा सके। इन अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। बसों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा जिससे बसों की लाइव लोकेशन की जानकारी मिल सकेगी। इसके अलावा सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन की व्यवस्था होगी।

संक्षिप्त समाचार

नीट परीक्षा में पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई की मांग

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान सीधी। नीट परीक्षा में पेपर लीक की घटना की निष्पक्ष जांच एवं कठोर कार्रवाई के लिए छात्र नेता दिव्यांश सिंह चौहान द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक नीट परीक्षा में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आने से लाखों छात्रों और उनके परिवारों का विश्वास टूट गया है। वर्षों की मेहनत और संघर्ष के बाद छात्र इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं लेकिन भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण उनका भविष्य खतरे में पड़ रहा है। श्री चौहान ने कहा है कि एक छात्र प्रतिनिधि होने के नाते मैं यह मांग करता हूं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जां कर दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोंकने हेतु परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाया जाए।

केंद्र एवं प्रदेश की जनकल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आवाहन

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा, हसनपुरः मंगलवार को हसनपुर विधानसभा 42 के ग्राम चंदन कोटा में बीजेपी जन कल्याण मंच की एक बैठक आयोजित की गई जिसमें केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का आवाहन किया गया, बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी जन कल्याण मंच अमरोहा के जिला उपाध्यक्ष बबलू सिंह सेन ने कहा कि अमरोहा जिले में बीजेपी जन कल्याण मंच जिला अध्यक्ष भीष्म सिंह खड़कवंशी के नेतृत्व में नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है, जिला अध्यक्ष भीष्म सिंह खड़कबंशी के नेतृत्व में आज संगठन से जुड़ने की लोगों में होड़ मची है अब तक संगठन में सैकड़ो लोग शामिल हो चुके हैं, उन्होंने बताया कि हमारे संगठन का उद्देश्य भाजपा की प्रदेश एवं केंद्र सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही प्रत्येक योजनाओं को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना है, वही आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार लानी है, साथ ही उन्होंने उपस्थित लोगों से संगठन से अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने का आवाहन किया, इस मौके पर भारी संख्या में गांव के नौजवान, बुजुर्ग एवं मातृशक्तियो ने बढ़ चढ़कर बैठक में भाग लिया।

बीजेपी जन कल्याण मंच की ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई

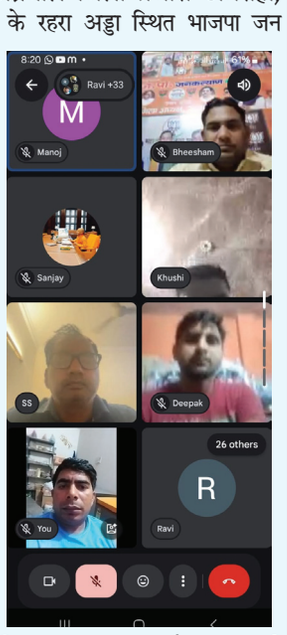

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा, हसनपुरः मंगलवार देर श्याम नगर के रहरा अड्डा स्थित भाजपा जन कल्याण मंच के जिला अध्यक्ष के कैंप कार्यालय पर संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक जूम एप के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की गई, बैठक में संगठन के दर्जनों पदाधिकारी ऑनलाइन बैठक में सम्मिलित हुए जिसमें अमरोहा जिले के जिला अध्यक्ष भीष्म सिंह खड़कवंशी ने बताया कि ऑनलाइन बैठक में बीजेपी जन कल्याण मंच के जिला स्तरीय पदाधिकारीयो आदि सहित संगठन के कई वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया, बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों और सामाजिक कार्य को लेकर विस्तृत चर्चा की बैठक के दौरान संगठन की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए एक जुट होकर काम करने पर जोर दिया गया, जिला अध्यक्ष भीष्म सिंह खड़कवंशी ने बैठक के माध्यम से कहा कि अपनी जड़ों से जुड़कर संगठन को और अधिक मजबूत बनाना होगा, साथ ही संगठनात्मक मजबूती के साथ-साथ जनता दरबार लगाने पर भी बल दिया, वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया जिले के हर ब्लॉक और गांव स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और नए सदस्य को जोड़ने पर विशेष बल दिया गया, बैठक के अंत में जिला अध्यक्ष भीष्म सिंह खड़क बंशी ने सभी से संगठन हित मे कार्य करने की अपील की।

प्रतिबंधित सोन नदी से रेत निकासी की खुली छूट

» सोन घड़ियाल एवं पुलिस पर लग रहे संरक्षण के आरोप

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले में इन दिनों प्रतिबंधित सोन नदी से रेत निकासी का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, सबसे ज्यादा यह कारोबार बहरी, रामपुर नैकिन एवं कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सोन नदी के घाटों से चल रहा है। सूत्र बताते हैं कि इस पूरे अवैध रेत उत्खनन में सोन घड़ियाल अभ्यारण्य एवं स्थानीय पुलिस की अहम भूमिका है, कारण कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों को दूरभाष पर सूचित किया जाता है तो कार्यवाही के बजाय उसका नाम जरूर रेत माफियाओं तक पहुंचा दिया जाता है। जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि की सोन नदी से अवैध रेत उत्खनन का कारोबार जिम्मेदार विभाग के आला अधिकारियों के संरक्षण में ही चल रहा है। उल्लेखनीय है कि सीधी जिले के अमिलिया, सिहावल, जमोड़ी, मझौली, खड्डी, रामपुर नैकिन एवं कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध रेत निकासी का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इस संबंध में स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस एवं वन अमले सहित सोन घड़ियाल अभ्यारण्य के आला अधिकारियों से शिकायत भी जाती है लेकिन किसी के द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जिसके चलते अब लोग यह कहने लगे हैं कि अवैध रेत निकासी का कारोबार विभागीय संरक्षण में धड़ल्ले से चल रहा है।

रेकी के लिए तैनात हैं गुर्गे

अवैध रेत का कारोबार करने वाले रेत माफियाओं द्वारा खनिज विभाग एवं राजस्व विभाग की कार्यवाही से बचने के लिए रेकी की टीम तैयार की गई है, जो विभिन्न मार्गों में मौजूद रहती हैं और जैसे ही किसी विभाग का वाहन इस मार्ग में प्रवेश करता है तत्काल मोबाइल फोन के माध्यम से सूचित कर दिया जाता है। उधर सूचना मिलते ही माफिया वाहनों के साथ मौके से रफू चक्कर हो जाते हैं, जिसके चलते इन पर कार्यवाही का शिकंजा नहीं कसा जा रहा है। ग्रामीणों की मानें तो एक तरफ अवैध उत्खनन करने वाले माफियाओं द्वारा जहां कनेक्टिंग मार्गों पर अपने आदमी बैठाए जा रहे हैं वहीं दूसरी तरफ माफियाओं के संबंध इतने अच्छे हैं कि पुलिस के बीट प्रभारी एवं सोन घड़ियाल अभ्यारण्य की टीम में शामिल लोगों द्वारा ही टीम आने की सूचना दे दी जाती हैं। जिसके चलते बड़े अधिकारी जब पहुंचते हैं तो उन्हें खाली हांथ ही लौटना पड़ता है।

श्रम कानूनों में बदलाव के लिए सीटू यूनियन ने मनाया विरोध दिवस

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख लोकतंत्र) लोकतंत्र की शान

सीधी। केंद्र सरकार द्वारा एक तरफा फैसला लेते हुए श्रमिक विरोधी 4 काले कानूनों को 8 मई को लागू कर दिया गया है, ज्ञात हो कि 21 नवम्बर 2025 को 29 श्रम कानूनों को खत्म कर 4 लेबर कोड बिल लाया गया था, जिसका उद्देश्य गरीब मजदूरों के हक को पूंजीपतियों के अधीन करना था,इस लेबर कोड बिल के आने से न्यूनतम वेतन, 8 घंटे के काम,निश्चित अवधि की नौकरी, कभी भी नौकरी से निकालने जैसी समस्याएं होगी, जिसके कारण गरीब मजदूरों को अपने परिवार के भरण पोषण और भविष्य की चिंता सता रही है। सरकार ने लेबर कोड के माध्यम से मजदूरों का पाने हक को पाने के लिए हड़ताल करने जैसे हकों पर सीधा हमला किया है। इसके विरोध में अल्ट्राटेक सीधी सीमेंट मझिगवा कारखाने के मेन गेट में सीटू यूनियन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में इकाई के अध्यक्ष तेज प्रताप दुबे, विक्रम सिंह, अरविन्द सिंह, संजीव मिश्रा, श्रवण द्विवेदी, बापू नाथ योगी, लल्ला सिंह, अरुण कुशवाहा, कमलेश शुक्ला सहित सैकड़ो श्रमिक उपस्थित रहें।

मिनी हाइवा ने बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत

» मासूम सहित तीन गंभीर घायल जिला अस्पताल में भर्ती

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले के पथरौला चौकी अंतर्गत बरवाही गांव में मंगलवार देर रात करीब 10 बजे तेज रफ्तार मिनी हाइवा ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक महिला और 5 साल के मासूम सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान बकवा निवासी आनंद बहादुर सिंह के रूप में हुई है। घायलों में रूद्र सिंह, अरुणा बसोर, संजय बसोर और आयुष बसोर शामिल हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल 108 एंबुलेंस को सूचना दी। 108 एंबुलेंस चालक मनोज यादव ने बताया कि सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे। उस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी, जबकि तीनों घायलों की हालत गंभीर थी। प्राथमिक इलाज के बाद सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल सीधी पहुंचाया गया।

इनका कहना है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए बुधवार सुबह मड़वास अस्पताल भेजा गया।देर रात होने के कारण पोस्टमार्टम नहीं हो सका था। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त मिनी हाइवा वाहन को जब्त कर लिया है। मामले में मर्ग कायम कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे की मुख्य वजह बताया जा रहा है। देवराज सिंह, चौकी प्रभारी पथरौला।

लीड्स 2025 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को मिला 'एग्जेम्प्लर' अवार्ड

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली/लखनऊ। लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर उत्तर प्रदेश ने देश में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स - लीड्स (LEADS) 2025* रैंकिंग में लैंडलॉक्ड राज्यों में सर्वोच्च "एग्जेम्प्लर (Exemplar)" पुरस्कार प्राप्त किया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ एवं अनुकरणीय प्रदर्शन करने वाला लैंडलॉक्ड (चारों ओर भूमि से घिरा) राज्य बनकर उभरा है। पिछले तीन साल (2022 से 2024) तक लगातार "अचीवर" रहने के बाद, इस साल शीर्ष पायदान पर राज्य की यह छलांग यहां के बेहतरीन कनेक्टिविटी नेटवर्क और प्रभावी नीतिगत सुधारों का सीधा परिणाम है। यह सम्मान बुधवार को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में आयोजित लीड्स 2025 रिपोर्ट एवं LEAPS (Logistics Excellence, Advancements & Performance Shield) 2025 पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश की ओर से यह पुरस्कार इन्वेस्ट यूपी के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शशांक चौधरी ने प्राप्त किया। वर्ष 2018 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईटी) द्वारा शुरू की गई 'लीड्स' पहल राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक राष्ट्रीय बेंचमार्किंग फ्रेमवर्क है। इस रैंकिंग में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवाएं, नियामकीय व्यवस्था तथा परिचालन दक्षता जैसे महत्वपूर्ण मानकों का मूल्यांकन किया जाता है। इन्वेस्ट यूपी के एसीईओ ने इस सफलता पर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप लॉजिस्टिक्स सेक्टर को राज्य की 'वन ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनाया गया है। 'उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति 2022' के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश का लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम अभूतपूर्व रूप से मजबूत हुआ है।

सरकार की नीतियों से अवगत करवाना प्रशिक्षण -अशोक गुर्जर

लोकतंत्र की शान, राजेंद्र करनाल के रिपोर्ट

करनालः पार्टी को संगठनात्मक दृष्टि से मजबूती प्रदान करने हेतु एवं 16 व 17 मई को करनाल में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण महाअभियान की तैयारियों को लेकर आज भाजपा जिला कार्यालय कर्ण कमल में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीण लाठर की अध्यक्षता में भाजपा जिला पदाधिकारियों की बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर सभी पदाधिकारियों को बैठक में मुख्य तौर पर मौजूद पानीपत जिला प्रभारी अशोक गुर्जर, जिलाध्यक्ष प्रवीण लाठर एवं करनाल जिला प्रभारी भारत भूषण जुआल का मार्गदर्शन मिला। इस मौके पर मुख्य तौर पर मौजूद पानीपत जिला प्रभारी अशोक गुर्जर ने बताया पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान (2026) भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया जा रहा एक व्यापक संगठनात्मक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से परिपक्व, अनुशासित और सांगठनिक रूप से सक्षम बनाना है। यह अभियान कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा (राष्ट्रवाद, अंत्योदय) और सरकार की नीतियों से अवगत कराकर उन्हें राष्ट्र पुनर्निर्माण के लिए तैयार करता है उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर से कार्यकर्ताओं को वैचारिक स्पष्टता, संगठनात्मक कौशल और समर्पण की भावना से परिपूर्ण करना है ताकि वे 'कर्मयोगी' बन सकें। उन्होंने बताया कि इस महाअभियान के तहत प्रदेश, जिला और मंडल स्तर पर कार्यशालाओं और प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन किया जा रहा है ताकि कार्यकर्ताओं को भाजपा की विचारधारा, अंत्योदय, राष्ट्र निर्माण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा सके जिससे प्रशिक्षित कार्यकर्ता समाज के अंतिम व्यक्ति तक पार्टी का संदेश पहुंचा सकें इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष संजय राणा, साहिल मदान, दीपक शर्मा, प्रियंका काठपाल, संयोगिता गुप्ता, नरेंद्र सिंह, जिला महामंत्री सुभाष कश्यप, मानव पुरी, जिला सचिव विकास कथूरिया, ऊषा रानी, सुमन नरवाल, मनमीत बावा, नवीन कुमार,जिला मीडिया प्रभारी डा अशोक कुमार,आई टी सेल प्रमुख विकास राणा, जिला प्रवक्ता शिव नाथ कपूर, जिला कार्यालय प्रमुख मदन गुर्जर, प्रमोद नागपाल,कोषाध्यक्ष मोनिक गर्ग एवं मुदित आर्य सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

खबर का असरः रिटायर शिक्षक को मिला चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ

खबर प्रकाशन के बाद जारी हुई लाभार्थियों की सूची

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ पाने के लिए कलेक्टर के यहां लिखित फरियाद करने वो सेवानिवृत्त शिक्षक भागवत प्रसाद मिश्रा का नाम आज जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी सूची में शामिल हो गया। सेवानिवृत्त शिक्षक भागवत प्रसाद मिश्रा ने बताया कि आज उनकी फरियाद एवं समस्या को लेकर मीडिया में खबर प्रकाशन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी सीधी द्वारा आनन-फानन में सूची जारी कर दी गई। जिसमें उनका नाम भी सूची के सरल क्रमांक 188 में शामिल है। इसके लिए सेवानिवृत्त शिक्षक ने मीडिया के प्रति कृतज्ञता जाहिर की। दरअसल जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आज 13 मई को चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान की सूची जारी की गई जिसमें सीधी जिले के 258 शिक्षकों का नाम शामिल है। इसमें कई ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षक भी शामिल हैं जिनके द्वारा 35 वर्ष तक नियमित सेवा पूर्ण की गई है।

C.B.S.E द्वारा घोषित इंटर परीक्षा परिणाम में H.S.S पब्लिक स्कूल हसनपुर के विद्यार्थियों ने मारी बाजी

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः बुधवार को सीबीएसई द्वारा घोषित इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा परिणाम 2026 में नगर के प्रतिष्ठित विद्यालय एचएसएस पब्लिक स्कूल हसनपुर के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का गौरव बढ़ाया, सीबीएसई द्वारा बुधवार को इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया जिसमें विद्यालय का परीक्षा परिणाम अत्यंत सराहनीय रहा, सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली विद्यालय की छात्रा पीहू अग्रवाल ने 95.6% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया जबकि सिराज अहमद ने 94.4% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा आन्य अग्रवाल ने 92.6% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान एवं एकांशी गोयल ने 91.6% अंक प्राप्त कर चतुर्थ स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया, विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों ने भी विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर सफलता हासिल की है इस शानदार परिणाम से विद्यालय परिवार में हर्ष का वातावरण है, उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत विद्यालय परिसर में हर्ष एवं उत्साह का वातावरण देखने को मिला, वही विद्यालय के प्रधानाचार्य अंकुर काशिव एवं प्रबंधक राजीव अग्रवाल ने मेधावी विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर उनकी सफलता पर शुभकामनाएं दी,उधर विद्यार्थियों एवं अभिभावकों ने भी इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है, इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य अंकुर काशिव ने कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों की मेहनत शिक्षकों के समर्पण तथा अभिभावकों के निरंतर सहयोग का परिणाम है उन्होंने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की, वही विद्यालय के प्रबंधक राजीव अग्रवाल ने विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया तथा सफल विद्यार्थियों उनके अभिभावको एवं शिक्षकों को इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं, इस मौके पर विद्यालय का समस्त स्टाफ छात्राएं मौजूद रहे।

रिश्तेदार ने घर से ले जाकर बुजुर्ग की कर दी हत्या

» आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई कराने भटक रहा पुत्र

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

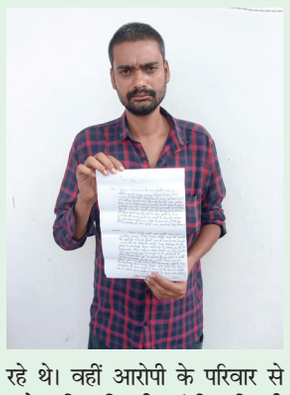

सीधी। जिले के पुलिस चौकी खड्डी अंतर्गत ग्राम खड्डी में एक रिश्तेदार द्वारा कार से बुजुर्ग को अपने घर ले जाकर सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी गई। जानकारी होने पर मृतक के पुत्र द्वारा पुलिस को सूचना देकर बुलाया गया। पोस्टमार्टम कार्रवाई के पश्चात भी पुलिस की विवेचना के अधर में लटकने से पीडित पुत्र द्वारा पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर को आवेदन देकर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गुहार लगाई गई है। तत्संबंध में धर्मेंद्र तिवारी निवासी ग्राम खड्डी कला ने बताया कि उसके पिता रामप्यारे तिवारी उम्र 65 वर्ष एसईसीएल कोलियरी कालरी जिला अनूपपुर से वर्ष 2023 में सेवानिवृत्त होकर अपने गृह ग्राम में आकर रह रहे थे। वहीं आरोपी के परिवार से जुड़े अनिल तिवारी एवं प्रिंस तिवारी पड़ोसी ग्राम खड्डी खुर्द के निवासी हैं। इनसे करीब 15 वर्ष पूर्व जमीनी विवाद चला था। किंतु वर्तमान में कोई विवाद नहीं था। अभी 1 अप्रैल 2026 की रात करीब 8 बजे रामप्यारे तिवारी अपने घर में अकेले थे। उसी दौरान अनिल तिवारी अपनी बलेनो कार से पहुंचे। कुछ समय तक सामान्य चर्चा इनके बीच चल रही थी। घर में मौजूद रामप्यारे के दोनो पुत्र किसी काम से गांव में ही कुछ समय के लिए चले गए थे। इसी दौरान अनिल तिवारी अपनी कार में बैठाकर रामप्यारे को अपने घर ले गए। रामप्यारे के साथ ही उनके कमरे में रखी संदूक पेटी भी कार में रखकर ले गए। घर में दोनो बच्चों के लौटने के बाद पिता के न मिलने पर उनके द्वारा अनिल तिवारी के मोबाइल पर फोन लगाया गया तो उनके द्वारा कहा गया कि मेरे साथ हैं एक घंटे में पहुंचा दूंगा। काफी देर तक पिता के न आने पर जब फिर अनिल को फोन किया गया तो उन्होने रिसीव नहीं किया। अगले दिन 2 अप्रैल को सुबह करीब 8:30 बजे अनिल तिवारी के घर ग्राम खड्डी खुर्द जब धर्मेन्द्र तिवारी पहुंचे तो वहां उनके पिता तखत में लेटकर कराह रहे थे। बात करने पर उन्होने पुत्र को बताया कि अनिल एवं प्रिंस ने उनके साथ काफी मारपीट की। इस पर पुत्र ने पिता को जल्द घर पहुंचाने के लिए कहा अन्यथा पुलिस को सूचना देने की बात कही। घर आकर धर्मेन्द्र तिवारी ने आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी और लोगों के सुझाव पर खड्डी पुलिस चौकी जाने की तैयारी कर रहे थे तभी प्रिंस तिवारी तथा मनीष गुप्ता कार में रामप्यारे तिवारी को लेटाकर पहुंचाया। देखने पर मालूम पड़ा कि रामप्यारे तिवारी की मौत हो चुकी है। जिसकी सूचना खड्डी पुलिस को दी गई। काफी विलंब से पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए लाश रामपुर नैकिन अस्पताल पहुंचाया गया। किंतु शाम हो जाने के कारण डॉक्टर द्वारा अगले दिन 3 अप्रैल की सुबह पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। पीड़ित धर्मेन्द्र तिवारी ने कहा है कि आरोपियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई न होने के कारण उनके द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है। पिताजी के साथ जो संदूक ले गए थे उसमें करीब 12 तोला सोने के जेवरात, 45 हजार नकदी एवं जमीन के कागजात आदि थे।

संक्षिप्त समाचार

ट्रम्प बोले- ईरान के खिलाफ हर हाल में जंग जीतेंगे, वे समझौता करेंगे या तबाह हो जाएंगे

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जारी जंग अमेरिका हर हाल में जीतेगा। चीन रवाना होने से पहले उन्होंने कहा, "ईरान या तो समझौता करेगा या फिर तबाह हो जाएगा।" ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका के पास हालात संभालने के लिए हर विकल्प मौजूद है। उन्होंने बताया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी बातचीत में ईरान युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट संकट पर भी चर्चा होगी। हालांकि, व्यापार बैठक का मुख्य मुद्दा रहेगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 74 दिनों की जंग में अब तक कम से कम 29 अरब डॉलर खर्च किए हैं। यह रकम सिर्फ हथियारों और सैन्य उपकरणों पर खर्च हुई है। इसमें सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान का खर्च शामिल नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कांग्रेस से अतिरिक्त रक्षा बजट की मांग की। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति बने रहने के लिए अमेरिका को 1.5 लाख करोड़ डॉलर की जरूरत है। शांति वार्ता अटकने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा तेजी आई। ब्रेंट क्रूड 107.68 डॉलर प्रति बैरल और WTI 101.61 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड (IRGC) ने कहा कि अब होर्मुज स्ट्रेट सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि 500 किलोमीटर तक फैला ऑपरेशन एरिया माना जाएगा। पाकिस्तान ने ईरानी विमानों को अपने एयरबेस पर जगह दी: CBS न्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान ने अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए ईरानी सैन्य विमानों को नूर खान एयरबेस पर पार्किंग की अनुमति दी। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में 4 हवाई हमले किए: इजराइल ने लेबनान के नबातियेह क्षेत्र के जेबचीत कस्बे पर लगातार 4 एयरस्ट्राइक कीं। मस्जिद के आसपास भी हमला हुआ और बाद में तोपों से गोलाबारी की गई।

भारतीय पर्यटकों के नेपाल प्रवेश पर प्रतिबंध की खबरों को पर्यटन बोर्ड ने बताया भ्रामक

काठमांडू। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने भारतीय पर्यटकों पर नए प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी फैल रही खबरों को भ्रामक और तथ्यहीन बताते हुए स्पष्ट किया है कि नेपाल सरकार ने भारतीय नागरिकों की यात्रा व्यवस्था में कोई नया बदलाव नहीं किया है। पर्यटन बोर्ड ने बुधवार को एक बयान में कहा कि कुछ भारतीय मीडिया संस्थानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर ऐसी गलत सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं कि नेपाल आने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए अनिवार्य पहचान पत्र, 30 दिन की समय सीमा तथा अधिक समय रुकने पर वाहनों की जब्ती जैसी नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। बोर्ड ने इन सभी दावों को पूरी तरह निराधार और भ्रम फैलाने वाला बताया। नेपाल सरकार ने स्पष्ट किया कि भारतीय पर्यटकों के नेपाल में रहने की अवधि को सीमित करने वाली कोई नई नीति लागू नहीं की गई है। साथ ही नेपाल और भारत के बीच लंबे समय से चली आ रही खुली सीमा व्यवस्था तथा द्विपक्षीय समझौतों में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

बयान में कहा गया है कि नेपाल और भारत के बीच ऐतिहासिक जनस्तरीय संबंध, सांस्कृतिक निकटता और पर्यटन सहयोग पहले की तरह मजबूत और कायम हैं। बोर्ड ने यह भी जानकारी दी कि नेपाल सरकार ने हाल ही में भारतीय और अन्य विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए एक नई ऑनलाइन प्रणाली शुरू की है। भन्सार विभाग द्वारा विकसित इस डिजिटल प्रणाली के माध्यम से निजी वाहनों से नेपाल आने वाले विदेशी नागरिक अब अस्थायी प्रवेश अनुमति और राजस्व भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार इस व्यवस्था का उद्देश्य सीमा नाकों पर प्रक्रिया को सरल बनाना, यात्रियों की असुविधा कम करना और पर्यटकों को बेहतर अनुभव प्रदान करना है। बोर्ड ने मीडिया संस्थानों, डिजिटल प्लेटफॉर्मों, पर्यटन व्यवसायियों और आम नागरिकों से अपुष्ट सूचनाएं साझा न करने तथा केवल नेपाल सरकार और नेपाल पर्यटन बोर्ड के आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। यह भी कहा गया है कि नेपाल भारतीय पर्यटकों सहित दुनिया भर के आगंतुकों के लिए सुरक्षित, मैत्रीपूर्ण और स्वागतयोग्य पर्यटन गंतव्य बना हुआ है।

पीएम मोदी की अपील के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी घटाया अपना काफिला

कोलकाता। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच ईंधन बचत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने आधिकारिक काफिले में शामिल वाहनों की संख्या कम करने का फैसला किया है। उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों को गैर जरूरी वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। बुधवार को भवानीपुर से विधायक पद की शपथ लेने के बाद विधानसभा परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को केवल आवश्यक वाहनों को ही काफिले में रखने को कहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा के साथ केंद्रीय सुरक्षा भी प्राप्त है। इस वजह से उनके काफिले में सामान्य तौर पर बड़ी संख्या में वाहन शामिल रहते हैं। हालांकि, प्रधानमंत्री की ईंधन बचत संबंधी अपील के बाद उन्होंने सुरक्षा प्रोटोकॉल बनाए रखते हुए काफिले को सीमित करने का निर्णय लिया। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण बढ़ते आर्थिक दबाव के मद्देनजर सरकारी अधिकारियों और आम नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने की अपील की थी। इसी पहल के तहत प्रधानमंत्री ने अपने काफिले में शामिल वाहनों की संख्या भी लगभग 50 प्रतिशत तक कम करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले में वाहनों की संख्या घटाकर इसी तरह का कदम उठाया है। बुधवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से विधायक के रूप में शपथ ली। उनके साथ कई मंत्रियों और नवनिर्वाचित विधायकों ने भी शपथ ग्रहण किया। शपथ दिलाने की प्रक्रिया प्रोटेम स्पीकर तापस राय ने संपन्न कराई। इस बीच भाजपा के कई विधायक भी प्रधानमंत्री की अपील का पालन करते नजर आए। कई भाजपा विधायक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बसों से विधानसभा पहुंचे। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, शीर्ष नेताओं द्वारा उठाए गए ये कदम पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक परिस्थितियों से उत्पन्न आर्थिक दबाव और बढ़ती ईंधन कीमतों को लेकर प्रतीकात्मक तथा प्रशासनिक प्रतिक्रिया के रूप में देखे जा रहे हैं।

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष ने साइकिल से कार्यालय पहुंचने का लिया संकल्प

नई दिल्ली। देश में ईंधन संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद मोदी द्वारा देश वासियों को दिए गए संदेश को आगे बढ़ाते हुए, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने पेट्रोल एवं डीज़ल के सीमित करने का निर्णय लिया है। इस पहल के अंतर्गत उन्होंने गुरुवार से साइकिल से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय अपने कार्यालय पहुंचने का संकल्प लिया है। इस कदम का उद्देश्य आम नागरिकों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति प्रेरित करना तथा पर्यावरण हितैषी जीवनशैली को प्रोत्साहित करना है। जमाल सिद्दीकी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ईंधन की बचत केवल आर्थिक विषय नहीं है, बल्कि यह देश की ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने देशवासियों से अपील की, कि वे भी दैनिक जीवन में संभव होने पर साइकिल, पैदल चलने या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और ऊर्जा संरक्षण में योगदान दें। मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी फैसल मुमताज़ ने बताया राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दिकी अपने सुरक्षाकर्मियों, सहायक, सहयोगी के साथ 3 गाड़ियों से ले चलते थे, अब सुरक्षाकर्मी, सहायक और सहयोगी सभी लोग साईकिल से उनके साथ चलेंगे । जमाल सिद्दिकी की यह पहल ऊर्जा संरक्षण के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने और समाज में सकारात्मक जागरूकता फैलाने का एक प्रयास है।

हिमंत बिस्व सरमा 2.0 सरकार : 26 मई को सदन में पेश होगा यूसीसी बिल

एजेंसी, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा के नेतृत्व वाली नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक बुधवार को सम्पन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गये। बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने आज से आधिकारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया है तथा मंत्रियों के विभागों की घोषणा शीघ्र की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैबिनेट ने 26 मई को सदन में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। हालांकि, जनजातीय समुदायों तथा सभी प्रकार की धार्मिक परंपराओं और रीति-रिवाजों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। प्रस्तावित यूसीसी में मुख्य रूप से विवाह की न्यूनतम आयु, संपत्ति अधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप तथा बहुविवाह जैसे विषय शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि असम विधानसभा का सत्र 21, 22, 25 और 26 मई को आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का संकल्प पत्र ही नई सरकार के संचालन का आधार बनेगा। सरकार ने दो लाख सरकारी नौकरियों के लक्ष्य को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव सभी विभागों के साथ चर्चा कर अगले पांच वर्षों में युवाओं को सरकारी रोजगार उपलब्ध कराने की रूपरेखा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

कैबिनेट ने महान गायक एवं सांस्कृतिक पुरोधा डॉ. भूपेन हजारिका की जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम को आगामी 8 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित करने का निर्णय लिया। साथ ही, कलाक्षेत्र में डॉ. भूपेन हजारिका का संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, जिस पर 32 करोड़ खर्च होंगे। इसमें से 13 करोड़ रुपये नॉर्थ ईस्ट काउंसिल द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, देवजीत लोन सैकिया को आगामी पांच वर्षों के लिए राज्य सरकार का महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है।

सरकार ने मितव्ययिता से जुड़े कई बड़े फैसले भी लिए हैं। अगले छह महीनों तक नए मंत्रियों को नई गाड़ियां नहीं दी जाएंगी। इसी अवधि में मंत्री, सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे। केवल चिकित्सकीय कारणों से ही विदेश जाने की अनुमति होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल से लेकर मंत्रियों और अधिकारियों तक के काफिले में वाहनों की संख्या कम की जाएगी। साथ ही, वर्ष 2025 की तुलना में पेट्रोल और डीजल पर सरकारी खर्च कम करने का लक्ष्य रखा गया है। विदेशी मुद्रा की बचत के उद्देश्य से अगले छह महीनों तक राज्य सरकार विदेशी सामान की खरीद नहीं करेगी। इस दौरान सभी सेमिनार और कार्यशालाएं केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएंगी।

मणिपुर के कांगपोकपी में उग्रवादियों ने घात लगाकर किया हमला, तीन की हुई मौत

एजेंसी, इंफाल

मणिपुर के कांगपोकपी ज़िले में संदिग्ध हथियारबंद उग्रवादियों द्वारा दो गाड़ियों पर घात लगाकर बुधवार को किए गए हमले में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, यह हमला कथित तौर पर कोटजिम और कोटलेन गांवों के बीच हुआ। सूत्रों ने बताया कि हमले के शिकार दो गाड़ियों में सफ़र कर रहे थे, तभी कथित तौर पर हथियारबंद हमलावरों ने उन्हें रोका और उन पर गोलियां चला दीं। घायलों को तुरंत पास के मेडिकल सेंटरों में ले जाया गया।

कूकी इनपी, मणिपुर ने राज्य के कोटज़िम और कोटलेन इलाकों के बीच कथित तौर पर घात लगाकर किए गए हमले में तीन कूकी-ज़ो चर्च नेताओं और नागरिकों की हत्या की कड़ी निंदा की है। उसने इस घटना को "कायरतापूर्ण और बर्बर हमला" बताया है, जिसका मकसद इस क्षेत्र में शांति प्रयासों को पटरी से उतारना है।

आज जारी एक बयान में, कूकी जनजातियों की शीर्ष संस्था कूकी इनपी ने आरोप लगाया कि यह घात लगाकर किया गया हमला जेडयूएफ-कामसन गुट और वीबीआईजी द्वारा किया गया था, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना के बाद सुरक्षा बल कथित तौर पर इलाके में पहुंच गए हैं और उन्होंने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने अभी तक पीड़ितों की पहचान या हमले के पीछे किस समूह का हाथ है, इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।

इस ताजा हिंसा ने मणिपुर के पहाड़ी ज़िलों में सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं, जहां पिछले एक साल में हथियारबंद झड़पों और हमलों की कई घटनाएं सामने आई हैं। इस घटना की जांच अभी जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार है।

नीट पेपर लीक पर युवा कांग्रेस विरोध प्रदर्शन

एजेंसी, नई दिल्ली

युवा कांग्रेस ने राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन की मांग की । नई दिल्ली में युवा कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हुए इस प्रदर्शन में जुटे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर काबू किया।

विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली युवा कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार देश में पेपर लीक रोकने में नाकाम हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) बनी है, तब से लगातार पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं। अदालतों ने भी इस पर संज्ञान लिया है। पहले विश्वविद्यालय और राज्य सरकारें परीक्षाएं कराती थीं, लेकिन अब एनटीए के भाजपा सरकार ने ऐसा भ्रष्ट तंत्र बना दिया है, जिसमें गरीब छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है।

अक्षय लाकड़ा ने कहा कि नीट पेपर लीक में ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं, जो खुद कोचिंग संस्थान चलाते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि पिछले दस साल में 89 पेपर लीक हुए, जिनमें चार बार नीट का पेपर लीक हुआ और 48 बार परीक्षाएं दोबारा करानी पड़ीं। पर किसी भी आरोपित को कठोर दंड नहीं दिया जा सका। यह घटनाएं शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। इस मौके पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली सह प्रभारी हैवरान कंसाना तथा राष्ट्रीय सचिव एहसान अहमद भी मौजूद रहे।

नागपुर एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण को मंजूरी, पीपीपी मॉडल पर होगा विकास

एजेंसी, नागपुर

नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास और आधुनिकीकरण को लेकर बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की उस जमीन की लीज अवधि बढ़ाने को मंजूरी दे दी है, जो पहले मिहान इंडिया लिमिटेड (एमआईएल) को दी गई थी। इस फैसले के बाद अब नागपुर एयरपोर्ट का संचालन और विकास अगले 30 वर्षों के लिए जीएमआर ग्रुप की सहयोगी कंपनी जीएमआर नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीएनआईएएल) को सौंपने का रास्ता साफ हो गया है।

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुए फैसले की जानकारी साझा करते हुए जीएमआर के अधिकारी ने बताया कि सरकार के इस निर्णय के साथ नागपुर एयरपोर्ट को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस करने और इसे मध्य भारत के प्रमुख विमानन एवं कार्गो केंद्र के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। एयरपोर्ट का विकास पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद जीएनआईएएल चरणबद्ध तरीके से एयरपोर्ट का विस्तार करेगा। योजना के अनुसार नागपुर एयरपोर्ट की यात्री क्षमता बढ़ाकर प्रति वर्ष 3 करोड़ तक पहुंचाई जाएगी। वर्तमान में मौजूदा टर्मिनल की क्षमता लगभग 20 लाख यात्री प्रतिवर्ष है। परियोजना के तहत अत्याधुनिक सुविधाओं वाला नया टर्मिनल बनाया जाएगा। पहले चरण में इसकी क्षमता 40 लाख यात्री सालाना होगी। इसके अलावा एक नया 4000 मीटर लंबा रनवे तैयार किया जाएगा, जबकि मौजूदा 3200 मीटर रनवे का विस्तार कर उसे 3600 मीटर तक बढ़ाया जाएगा। नागपुर एयरपोर्ट के विकास की प्रक्रिया वर्ष 2009 में शुरू हुई थी, जब एएआई और महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी (एमएडीसी) ने मिलकर मिहान इंडिया लिमिटेड का गठन किया था। इसमें एएआई की 49 प्रतिशत और एमएडीसी की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी तय की गई थी। हालांकि एयरपोर्ट की संपत्तियां उसी वर्ष एमआईएल को हस्तांतरित कर दी गई थीं, लेकिन जमीन सीमांकन विवादों के कारण लीज डीड में देरी हुई। बाद में एएआई की जमीन 6 अगस्त 2039 तक के लिए एमआईएल को लीज पर दी गई थी। वर्ष 2016 में एमआईएल ने पीपीपी मॉडल पर एयरपोर्ट संचालन के लिए वैश्विक निविदा जारी की थी, जिसमें जीएमआर एयरपोर्ट लि. सबसे बड़ी बोलीदाता बनी। बाद में निविदा रद्द होने पर जीएमआर ने बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय और बाद में उच्चतम न्यायालय ने जीएमआर के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद 8 अक्टूबर 2024 को एमआईएल और जीएमआर के बीच रियायत समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

मिहान परियोजना के तहत नागपुर को देश के प्रमुख एयर कार्गो हब के रूप में विकसित करने की योजना है। विस्तार के बाद एयरपोर्ट की कार्गो हैंडलिंग क्षमता 9 लाख टन प्रतिवर्ष तक पहुंचने का अनुमान है। इससे कृषि उत्पाद, फार्मा और विनिर्माण क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। फिलहाल नागपुर से मुंबई, दिल्ली, पुणे समेत कुछ घरेलू शहरों और कतर-शारजाह के लिए सीधी उड़ानें संचालित होती हैं।

सीबीआई ने उत्तराखंड के एलयूसीसी चिटफंड घोटाले में पांच आरोपितों को किया गिरफ्तार

एजेंसी, नई दिल्ली

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उत्तराखंड के लोनी अर्बन बहु-राज्यीय ऋण और बचत सहकारी समिति (एलयूसीसी) चिटफंड घोटाले में पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में मुख्य सरगना सुशील गोखरू के साथ राजेंद्र सिंह बिष्ट, तरुण कुमार मौर्य, गौरव रोहिल्ला और ममता भंडारी शामिल हैं। इन्हें देश के अलग-अलग स्थानों से पकड़ा गया।

सीबीआई ने बताया कि मामला एलयूसीसी से जुड़ा है। वर्ष 2025 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इस घोटाले से संबंधित सभी प्राथमिकी सीबीआई को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। इसके बाद सीबीआई ने 26 नवंबर 2025 को भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता, उत्तराखंड जमाकर्ताओं के हित संरक्षण अधिनियम और अनियमित जमा योजनाओं पर रोक लगाने वाले अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया।

जांच में सामने आया है कि इस घोटाले में राज्य के एक लाख से अधिक निवेशकों को विभिन्न अनियमित जमा योजनाओं में पैसा लगाने के लिए लालच दिया गया। कुल निवेश लगभग 800 करोड़ रुपये का अनुमानित है, जिसमें से आंशिक भुगतान किया गया, लेकिन धोखाधड़ी की राशि 400 करोड़ रुपये से अधिक है। सीबीआई ने बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपित समीर अग्रवाल और उनकी पत्नी सानिया अग्रवाल विदेश भाग गए हैं। इनके खिलाफ नोटिस और परिपत्र जारी किए गए हैं। एजेंसी ने तकनीकी निगरानी और स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर विशेष टीम गठित कर आरोपितों को पकड़ने की कार्रवाई की।

जांच में यह भी पता चला है कि आरोपितों ने अपराध से अर्जित धन से कई अचल संपत्तियां खरीदी हैं। इन संपत्तियों का विवरण उत्तराखंड सरकार के वित्त सचिव को भेजा गया है, ताकि इन्हें जब्त कर पीड़ित निवेशकों को अनियमित जमा योजनाओं पर रोक अधिनियम 2019 के प्रावधानों के तहत वितरित किया जा सके। गिरफ्तार आरोपितों को सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। मामले की जांच जारी है।

अरुणाचल में तस्करी का भंडाफोड़, 1.20 करोड़ की गैंडे के सींग समेत चार गिरफ्तार

एजेंसी, ईटानगर

अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले के होलोंगी क्षेत्र में वन विभाग और बालिजान पुलिस की संयुक्त अभियान चलाया।बालिजान पुलिस और होलोंगी वन अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई में संदिग्ध गैंडे के सींग की तस्करी में शामिल चार लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने आरोपितों के कब्जे से एक संदिग्ध गैंडे का सींग भी बरामद किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1.20 करोड़ बताई जा रही है। होलोंगी वन अधिकारी नबम राकेश ने बुधवार को बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर गैंडे के संदिग्ध सींग को बेचने की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर अधिकारियों ने ग्राहक बनकर तस्करों से संपर्क किया और असम-अरुणाचल सीमा क्षेत्र के होलोंगी में मिलने की योजना बनाई। उन्होंने बताया कि पहली बैठक सफल नहीं हो सकी, लेकिन दूसरी बैठक 12 मई को होलोंगी नदी क्षेत्र में तय की गई। इस दौरान अधिकारियों ने दो लोगों को हिरासत में लिया। उनकी निशानदेही पर मुख्य तस्कर के घर में तलाशी अभियान चलाया गया, जहां से एक संदिग्ध गैंडे का सींग बरामद किया गया। वन अधिकारी के अनुसार, आरोपित इस सींग को करीब 1.20 करोड़ रुपये में बेचने की योजना बना रहे थे। कार्रवाई के बाद चारों आरोपितों को आगे की जांच के लिए बालिजान पुलिस को सौंप दिया गया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान हेमंतो दास, रोमेन कोली, हमरजीत नारजरी और अजयसिंह देओमारी के रूप में हुई है। सभी आरोपी असम के बिस्वनाथ जिले के निवासी बताए गए हैं। पुलिस अधीक्षक (एसपी) पापुम पारे तारू गुसार ने पुलिस और वन विभाग की टीम को सफल अभियान के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यदि यह संदिग्ध गैंडे का सींग ईटानगर पहुंच जाता, तो तस्कर स्थानीय लोगों को ठगी का शिकार बना सकते थे। एसपी ने यह भी बताया कि हेमंतो दास एक आदतन शिकारी और तस्कर है, जिसके खिलाफ वन्यजीव अपराध से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। वह हाल ही में असम की जेल से एक वन्यजीव मामले में रिहा हुआ था।

अमित शाह 16-17 मई को गुजरात दौरे पर, अहमदाबाद और गांधीनगर में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल

अहमदाबाद। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। वह 16-17 मई को अहमदाबाद और गांधीनगर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वह अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) के नवनिर्वाचित पार्षदों से मुलाकात करेंगे। गांधीनगर महानगर पालिका के जन सम्पर्क अधिकारी ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की पुष्टि की है। अमित शाह अहमदाबाद और गांधीनगर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के लिए निगम अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। 16 मई को शाह अहमदाबाद के दक्षिण-पश्चिम जोन कार्यालय में गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में करोड़ों रुपये के विकास कार्य, तालाबों के इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, मानसून के दौरान "मिशन 5 मिलियन ट्री" अभियान समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिकारियों के साथ चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 17 मई को मधुर डेयरी के नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। डेयरी के चेयरमैन डॉ शंकर सिंह राणा के अनुसार 17 मई को केंद्रीय मंत्री गांधीनगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी मंडली द्वारा संचालित मधुर डेयरी के नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। चिलोड़ा के निकट दशेला गांव के पास बने इस नए प्लांट का उद्घाटन करने के बाद वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम दोपहर एक बजे आयोजित किया गया है। गृह मंत्री पूरे मिल्क प्लांट का निरीक्षण भी करेंगे।

विधानसभा चुनाव 2021 के हिंसा मामलों की फिर होगी जांच, शुभेंदु ने दिए केस दोबारा खोलने के निर्देश

एजेंसी, कोलकाता

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े मामलों की दोबारा समीक्षा और जांच कराने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों को आदेश जारी किया है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को बताया कि अवैध पशु तस्करी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी आदेश में कहा गया है कि चुनाव बाद हिंसा से जुड़े मामलों की जांच को लेकर गंभीर शिकायतें मिली हैं। आदेश में कहा गया, "2021 विधानसभा चुनाव के बाद आपके अधिकार क्षेत्र में दर्ज राजनीतिक हिंसा के पुराने मामलों की उचित कानूनी कार्रवाई के लिए समीक्षा की जाए।" सरकार ने निर्देश दिया है कि 2021 चुनाव बाद हिंसा मामलों में दाखिल अंतिम रिपोर्टों की सावधानीपूर्वक जांच की जाए और जहां जांच में किसी प्रकार की लापरवाही या कमी पाई जाए, वहां मामलों को दोबारा खोलकर विस्तृत जांच की जाए। आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन मामलों में प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन प्रारंभिक जांच में संज्ञेय अपराध सामने आते हैं, वहां नए मामले दर्ज किए जा सकते हैं। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को इस पूरी प्रक्रिया की व्यक्तिगत निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही आरोपपत्र दाखिल होने के बाद मुकदमों की नियमित निगरानी करने को भी कहा गया है। उल्लेखनीय है कि, 2021 विधानसभा चुनाव में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापक हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं। भाजपा ने उस चुनाव में 77 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल किया था। वर्ष 2016 में पार्टी के पास केवल तीन सीटें थीं। चुनाव बाद हिंसा के दौरान हत्या, दुष्कर्म, तोड़फोड़, आगजनी और भाजपा कार्यकर्ताओं तथा उनके परिवारों पर हमले के कई आरोप सामने आए थे। इन मामलों को लेकर मामला बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय पहुंचा था, जहां गंभीर हत्या और दुष्कर्म के मामलों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने का आदेश दिया गया था। इनमें से कई मामले अब भी लंबित हैं और पीड़ित न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद अब सरकार ने ऐसे मामलों को दोबारा खोलने और उनकी समीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

डिजिटल युग में भारत का निर्णायक मोड़- "प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड सिद्धांत बनाम "परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड सिद्धांत" से उभरता नया भारत -व्यापक समग्र विश्लेषण

लोकतंत्र की शान

» इतिहास गवाह है कि कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब सही नीतिगत निर्णय किसी राष्ट्र की दिशा बदल देते हैं

» कृत्रिम बुद्धिमत्ता,डिजिटल गवर्नेंस डेटा- आधारित निर्णय प्रणाली, ऑटोमेशन,रोबोटिक्स, इंडस्ट्री 4.0 में अब वही राष्ट्र भविष्य की आर्थिक शक्ति बनेंगे, जो परिवर्तन को तीव्र गति से संस्थागत रूप देंगे -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया- वैश्विक स्तरपर इक्कीसवीं सदी का तीसरा दशक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए केवल तकनीकी परिवर्तन का दौर नहीं,बल्कि शासन, व्यापार और विकास की अवधारणाओं के पुनर्निर्माण का काल बन चुका है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता,डिजिटल गवर्नेंस, डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली, ऑटोमेशन,रोबोटिक्स, इंडस्ट्री 4.0 और ग्लोबल सप्लाई चेन के पुनर्गठन ने दुनिया के सामने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब वही राष्ट्र भविष्य की आर्थिक शक्ति बनेंगे, जो परिवर्तन को केवल स्वीकार नहीं करेंगे,बल्कि उसे तीव्र गति से संस्थागत रूप देंगे। आज वैश्विक प्रतिस्पर्धा केवल प्राकृतिक संसाधनों या पारंपरिक औद्योगिक उत्पादन पर आधारित नहीं रही, बल्कि यह उस क्षमता पर निर्भर हो गई है जिसके माध्यम से कोई देश अपने प्रशासनिक ढांचे, नियामकीय प्रणाली और नवाचार संस्कृति को तेजी से आधुनिक बना सके। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क्रि यही कारण है कि अमेरिका,चीन,दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जापान और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं लगातार अपने प्रशासनिक मॉडल को फैसिलिटेटर स्टेट में परिवर्तित कर रही हैं, जहाँ सरकार नियंत्रणकर्ता कम और सक्षम बनाने वाली संस्था अधिक बनती जा रही है। इसी वैश्विक पृष्ठभूमि में भारत भी एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है,जहाँ वह लाइसेंस राज की पुरानी मानसिकता से बाहर निकलकर विश्वास आधारित शासन की नई अवधारणा को संस्थागत रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 11 से 12 मई 2026 को आयोजित सीआईआई वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन में नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा द्वारा दिया गया वक्तव्य केवल एक प्रशासनिक सुधार की घोषणा नहीं था, बल्कि यह भारत की भविष्य की आर्थिक दर्शनशास्त्र का संकेत भी था। इंस्टीट्यूशनलाइजिंग रिफॉर्म, बिल्डिंग द स्ट्रक्चरल फाउंडेशन फॉर इंडिया' फ्यूचर इकॉनमी विषय पर बोलते हुए उन्होंने जिस परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड मॉडल की चर्चा की, वह वस्तुतःभारत कीनियामकीय मानसिकता में क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रतीक है। दशकों तक भारत की आर्थिक प्रणाली प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड सिद्धांत पर चलती रही, अर्थात किसी भी व्यापारिक गतिविधि, उद्योग, सेवा या निवेश को प्रारंभ करने से पहले सरकारी अनुमति लेना आवश्यक माना जाता था। इससे उद्यमिता, नवाचार और उत्पादन क्षमता पर भारी दबाव बना रहता था। अब पहली बार भारत का नीति-निर्माण तंत्र यह स्वीकार करता दिखाई दे रहा है कि हर गतिविधि को पहले संदेह की दृष्टि से देखने के बजाय उसे स्वाभाविक रूप से अनुमति प्राप्त मानना चाहिए, जब तक कि वह स्पष्ट रूप से कानून द्वारा प्रतिबंधित न हो। यह परिवर्तन केवल भाषाई नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक सोच के पुनर्जन्म का संकेत है। साथियों बात अगर हम विश्व इकोनॉमी की करें तो आज का विश्व स्पीड इकॉनमी का विश्व बन चुका है। डिजिटल इन्नोवेशन पल-पल परिस्थितियों को बदल रहा है। जिस तकनीक को विकसित होने में पहले एक दशक लगता था, वह अब कुछ महीनों में वैश्विक बाजार का स्वरूप बदल देती है। ऐसे समय में यदि कोई देश अभी भी अनुमति, फाइल, क्लियरेंस और लाइसेंस की जटिल प्रक्रिया में उलझा रहेगा, तो वह वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट जाएगा। यही कारण है कि भारत अब अपनी नीतियों को कंट्रोल एंड रेगुलेशन से फैसिलिटेशन एंड ट्रस्ट की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है। राजीव गौबा ने रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल शब्द का उपयोग करते हुए इस समस्या को बेहद प्रभावी ढंग से परिभाषित किया। जैसे शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल रक्त प्रवाह को बाधित कर देता है, वैसे ही अत्यधिक नियम, अनावश्यक लाइसेंस, बार-बार नवीनीकरण और निरीक्षण आर्थिक गतिविधियों की गति को रोक देते हैं। भारत लंबे समय तक इसी "नियामकीय कोलेस्ट्रॉल" से जूझता रहा। उद्योगों को व्यापार शुरू करने के लिए दर्जनों विभागों से अनुमति लेनी पड़ती थी। छोटे और मध्यम उद्योगों का बड़ा हिस्सा अनुपालन और लाइसेंसिंग के बोझ तले दबा रहता था। परिणामस्वरूप उद्यमिता की ऊर्जा उत्पादन या नवाचार में लगने के बजाय प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सटीकता से नष्ट हो जाती थी। साथियों, नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत नया दृष्टिकोण इस पूरी संरचना को बदलने का प्रयास है। सरकार अब यह मान रही है कि उद्यमी अपराधी नहीं होते, बल्कि आर्थिक विकास के साझेदार होते हैं। जन विश्वास की अवधारणा इसी सोच का विस्तार है। यह वह विचार है जिसमें शासन नागरिकों और उद्योगों को संदेह की दृष्टि से नहीं, बल्कि भागीदार की तरह देखता है। इसी दिशा में 42,000 से अधिक अनुपालनों को हटाया जाना और लगभग 3,700 प्रावधानों का अपराधमुक्त किया जाना ऐतिहासिक कदम माना जा सकता है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में इतने बड़े स्तर पर नियामकीय सरलीकरण केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि आर्थिक संस्कृति में परिवर्तन का प्रतीक है। इससे यह संदेश जाता है कि सरकार अब उद्यमिता को नियंत्रित करने के बजाय प्रोत्साहित करना चाहती है। साथियों, यह परिवर्तन केवल आर्थिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है। दशकों तक भारतीय प्रशासनिक प्रणाली "स्टेट नोज बेस्ट" के सिद्धांत पर आधारित रही। सरकार तय करती थी कि कौन क्या उत्पादन करेगा, कितना उत्पादन करेगा और किन शर्तों पर करेगा। उदारीकरण के बाद कुछ बदलाव अवश्य आए, लेकिन लाइसेंसिंग संस्कृति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। अब पहली बार भारत एक ऐसे मॉडल की ओर बढ़ रहा है जहाँ नागरिक और उद्योग को अधिक स्वतंत्रता दी जा रही है। यह उसी प्रकार का परिवर्तन है जैसा 1980 और 1990 के दशक में दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और चीन ने किया था, जहाँ सरकारों ने उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नियामकीय बाधाओं को कम किया और उत्पादन को वैश्विक बाजारों से जोड़ा।हालांकि केवल नियमों को सरल बना देना पर्याप्त नहीं होगा। राजीव गौबा ने जिस दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान दिलाया, वह है अनुसंधान एवं विकास यानी आऱ एंड डी में निवेश।भारत आज भी अपने जीडीपी का केवल लगभग 0.7 प्रतिशत ही अनुसंधान और विकास पर खर्च करता है, जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाएं 2 से 4 प्रतिशत तक निवेश करती हैं। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि भारत में निजी क्षेत्र का योगदान केवल लगभग 36 प्रतिशत है। यदि भारत को वास्तव में वैश्विक इनोवेशन हब बनना है, तो उसे केवल मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि उसे तकनीकी नेतृत्व भी स्थापित करना होगा।सेमीकंडक्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, हरित ऊर्जा, बायोटेक्नोलॉजी और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में स्वदेशी तकनीक विकसित किए बिना कोई भी राष्ट्र दीर्घकालिक आर्थिक शक्ति कभी भी नहीं बन सकता। साथियों, आज दुनिया उस दौर में प्रवेश कर चुकी है जहाँ तकनीकी आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बन गई है। अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे समय में भारत के लिए केवल विदेशी तकनीक का उपभोक्ता बने रहना पर्याप्त नहीं होगा। उसे अपनी बौद्धिक संपदा, अपने पेटेंट, अपनी डिज़ाइन क्षमता और अपने अनुसंधान संस्थानों को वैश्विक स्तर तक ले जाना होगा। इसके लिए उद्योग और शिक्षा जगत के बीच गहरा सहयोग आवश्यक होगा। भारत की बड़ी समस्या यह रही है कि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों के बीच समन्वय अपेक्षाकृत कमजोर रहा है। यदि भारत को वास्तव में "मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन हब" बनना है, तो यह दूरी कम करनी होगी।इसी प्रकारस्किलिंग का प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंडस्ट्री 4.0 केवल मशीनों का युग नहीं, बल्कि अत्यधिक कुशल मानव संसाधन का युग है। यदि निर्माण क्षेत्र के केवल 20 प्रतिशत और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के केवल 1 प्रतिशत श्रमिक ही औपचारिक रूप से प्रशिक्षित हैं, तो यह भारत की विकास यात्रा के सामने गंभीर चुनौती है। विश्व अर्थव्यवस्था तेजी से ऑटोमेशन, डिजिटल प्रोसेस और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रही है। ऐसे में बिना प्रशिक्षित कार्यबल के भारत अपनी जनसंख्या को जनशक्ति में परिवर्तित नहीं कर पाएगा। इसलिए उद्योग आधारित स्किलिंग मॉडल की आवश्यकता है, जिसमें प्रशिक्षण सीधे बाजार और तकनीकी जरूरतोंसटीकता से जुड़ा हो। साथियों, भारत की वर्तमान स्थिति एक अवसर और चुनौती दोनों का मिश्रण है। अवसर इसलिए क्योंकि वैश्विक परिस्थितियां भारत के पक्ष में हैं। चुनौती इसलिए क्योंकि यदि यह अवसर चूक गया, तो आने वाले दशकों में प्रतिस्पर्धा और कठिन हो जाएगी। राजीव गौबा का यह कथन कि हर देश के पास मौके के पल होते हैं, और भारत आज उनमें से एक है वस्तुतः इसी वास्तविकता को दर्शाता है। इतिहास गवाह है कि कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब सही नीतिगत निर्णय किसी राष्ट्र की दिशा बदल देते हैं। 1991 का आर्थिक उदारीकरण भारत के लिए ऐसा ही क्षण था। अब 2026 में विश्वास आधारित नियामकीय व्यवस्था की ओर बढ़ना एक नए आर्थिक युग की शुरुआत साबित हो सकता है।यह भी महत्वपूर्ण है कि भारत की विकास रणनीति अब केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रह सकती। सरकार अकेले आर्थिक महाशक्ति नहीं बना सकती। इसके लिए उद्योग, स्टार्टअप, विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और नागरिक समाज सभी को साझेदार बनना होगा। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम पहले ही दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुँच चुका है। डिजिटल भुगतान और फिनटेक क्रांति ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय नवाचार वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकता है। अब आवश्यकता इस बात की है कि यही ऊर्जा मैन्युफैक्चरिंग, डीप टेक, हरित ऊर्जा और उन्नत अनुसंधान के क्षेत्रों में भी दिखाई दे। साथियों, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत का यह परिवर्तन उस समय हो रहा है जब दुनिया की सप्लाई चेन पुनर्गठित हो रही हैं। कोविड-19 महामारी, रूस-यूक्रेन संघर्ष, अमेरिका- चीन व्यापार युद्ध और भू- राजनीतिक तनावों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपनी उत्पादन रणनीति बदलने के लिए मजबूर किया है। कंपनियां अब चाइना प्लस वन रणनीति पर काम कर रही हैं और ऐसे देशों की तलाश कर रही हैं जहाँ राजनीतिक स्थिरता, विशाल बाजार, कुशल जनशक्ति और डिजिटल अवसंरचना उपलब्ध हो। भारत के पास ये सभी कारक मौजूद हैं। राजीव गौबा ने सही कहा कि भारत के पास डेमोग्राफिक शक्ति, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट स्केल और राजनीतिक प्रतिबद्धता का अनूठा संयोजन है। दुनिया की सबसे युवा आबादी, तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जैसी डिजिटल क्रांति, आधार आधारित पहचान प्रणाली, और विशाल उपभोक्ता बाजार भारत को वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहे हैं।किन्तु केवल संभावनाएं पर्याप्त नहीं होतीं। यदि प्रशासनिक ढांचा धीमा और जटिल रहेगा, तो निवेशक अन्य देशों की ओर चले जाएंगे। इसलिए परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड मॉडल का वास्तविक उद्देश्य भारत को निवेश और नवाचार के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। यह मॉडल उद्यमियों को परमिशन सीकिंग संस्कृति से बाहर निकालकर डूइंग बिजनेस संस्कृति की ओर ले जाता है। लंबे समय तक भारतीय उद्यमियों की ऊर्जा का बड़ा हिस्सा सरकारी अनुमतियों, निरीक्षणों और रिन्यूअल में खर्च होता रहा। अब सरकार यह व्यवस्था बनाना चाहती है कि जहाँ तक संभव हो, उद्योग स्वयं-प्रमाणन और थर्ड-पार्टी निरीक्षण के आधार पर कार्य करें, जबकि सरकार केवल उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करे जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वास्थ्य या गंभीर पर्यावरणीय जोखिम जुड़े हों। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क्रि परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि शासन दर्शन का परिवर्तन है। यह नागरिक और राज्य के संबंधों को पुनर्परिभाषित करता है। यह बताता है कि सरकार का कार्य हर गतिविधि को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें नवाचार, उद्यमिता और आर्थिक गतिविधियां स्वाभाविक रूप से विकसित हो सकें। यदि यह मॉडल प्रभावी ढंग से लागू होता है, तो भारत न केवल व्यापार सुगमता की रैंकिंग में आगे बढ़ेगा, बल्कि वह वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक विश्वसनीय उत्पादन और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित हो सकेगा।2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का भारत का सपना केवल जीडीपी के आँकड़ों से पूरा नहीं होगा। इसके लिए प्रशासनिक मानसिकता, नियामकीय संस्कृति और आर्थिक सोच में गहरे बदलाव आवश्यक होंगे। आज भारत उसी परिवर्तन के द्वार पर खड़ा दिखाई देता है। डिजिटल युग की तेज़ रफ्तार दुनिया में अब वही राष्ट्र आगे बढ़ेंगे, जो अपने नागरिकों और उद्यमियों पर भरोसा करेंगे, नवाचार को स्वतंत्रता देंगे और शासन को बाधा नहीं बल्कि सहयोगी बनाएंगे। भारत यदि इस दिशा में निरंतरता बनाए रखता है, तो आने वाले वर्षों में वह केवल दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था का एक केंद्रीय स्तंभ भी बन सकता है।

-संकलनकर्ता लेखक
- क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी)
एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र
9226229318

गाली जब स्वैग बन जाए, तो समझिए समाज अभद्र हो चला है

लेखक- दिलीप कुमार पाठक

आज 14 मई है। कैलेंडर कहता है कि आज राष्ट्रीय शालीनता दिवस है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि क्या अब शालीन रहने के लिए भी कोई खास दिन तय करना पड़ेगा? लेकिन अपने आसपास की डिजिटल दुनिया, सोशल मीडिया के कमेंट बॉक्स और टीवी बहसों नेताओं के भाषण या आसपास के शोर को देखिए, तो अहसास होगा कि शायद आज के दौर में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम तरक्की तो बहुत कर रहे हैं, चांद पर पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारी जुबान और व्यवहार से तमीज का रंग उतरता जा रहा है। खासकर इंटरनेट की दुनिया में तो ऐसा लगता है जैसे बदतमीजी करना ही नया फैशन या कूल दिखने का जरिया बन गया है। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसकी बोली से होती है। शब्द इंसान के भीतर के संस्कारों का आईना होते हैं। लेकिन आज की हकीकत कुछ और ही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स ने हमें एक नकाब दे दिया है। मोबाइल स्क्रीन के पीछे छिपे हम लोग खुद को बहुत बड़ा सूरमा समझने लगे हैं। हम वो बातें बड़ी आसानी से लिख देते हैं, जो शायद किसी के सामने खड़े होकर कहने की हिम्मत न हो। अगर किसी की बात हमें पसंद नहीं आती, तो हम उसे अपनी बात तर्क से समझाने के बजाय सीधा गाली-गलौज पर उतर आते हैं। उसे नीचा दिखाने के लिए उसके परिवार को बीच में ले आते हैं या उसे कोई नफरत भरा टैग दे देते हैं। यह जो ट्रोल कल्चर बढ़ रहा है, उसने हमारे समाज से संवाद की मिठास को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि अब अपशब्द बोलना एक तरह की बहादुरी मान लिया गया है। इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारी आज की लोकप्रिय संस्कृति का भी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आने वाली वेब सीरीज हो या स्टैंड-अप कॉमेडी, वहां गालियों को संवाद का जरूरी हिस्सा बना दिया गया है। जब बड़े पर्दे पर या मोबाइल स्क्रीन पर नामी सितारे गाली देते हैं, तो हमारे घर के बच्चों को लगता है कि शायद यही आज की आधुनिक भाषा है। उन्हें लगता है कि तमीज और अदब से बात करना तो पुराने जमाने के लोगों का काम है। नतीजा यह है कि आज का युवा वर्ग अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए तर्कों का नहीं, बल्कि अभद्र शब्दों का सहारा ले रहा है। उन्हें लगता है कि जो जितना तीखा और गंदा बोलेगा, वह उतना ही प्रभावशाली दिखेगा। सिर्फ सोशल मीडिया ही क्यों, हमारी टीवी बहसों को देख लीजिए। वहां जो प्रवक्ता जितनी जोर से चिल्लाता है और दूसरे को बोलने से रोकता है, उसे ही दमदार मान लिया जाता है। हमने एक ऐसी धारणा बना ली है कि जो विनम्र है, वो कमजोर है और जो बदतमीज है, वो ताकतवर। जबकि सच तो यह है कि चिल्लाने के लिए सिर्फ फेफड़ों का शोर चाहिए, लेकिन शांत रहकर अपनी बात मजबूती और गरिमा के साथ कहने के लिए बहुत बड़े आत्म-नियंत्रण की जरूरत होती है। शालीनता का मतलब डरना या चुप रहना कतई नहीं है। हमारे देश के बड़े-बड़े महापुरुषों ने दुनिया बदल दी, सत्ता की चूलें हिला दीं, लेकिन उनकी भाषा में कभी गन्दगी नहीं दिखी। गांधी जी, नेहरू जी, शास्त्री जी या कलाम साहब जैसे लोगों की बातों में वजन था, कड़वाहट नहीं। उनके विरोध में भी एक शालीनता थी, जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती थी। आज हम इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया से जुड़ तो गए हैं, लेकिन एक-दूसरे के दिलों के लिए जगह खोते जा रहे हैं। कीबोर्ड पर टाइप करती हमारी उंगलियां अक्सर यह भूल जाती हैं कि फोन के दूसरी तरफ भी एक जीता-जागता इंसान बैठा है, उसके भी जज्बात हैं।

प्रवासी मज़दूरों के लिए नई नीति और नई सोच की आवश्यकता

सैयद इसरार हुसैन

भारत की अर्थव्यवस्था की वास्तविक शक्ति यदि किसी वर्ग में दिखाई देती है, तो वह देश के करोड़ों प्रवासी मज़दूर हैं। निर्माण स्थलों से लेकर फैक्ट्रियों तक, खेतों से लेकर परिवहन और होटल उद्योग तक—देश की विकास यात्रा में इन श्रमिकों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। रोज़गार और बेहतर जीवन की तलाश में लाखों लोग हर वर्ष एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर पलायन करते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में श्रमिक दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने पहुंचते हैं। विडंबना यह है कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले यही श्रमिक आज भी सबसे अधिक असुरक्षित जीवन जीने को मजबूर हैं। भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए उन्हें निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। कोविड-19 महामारी के दौरान देश ने वह दर्दनाक दृश्य देखा, जब लाखों प्रवासी मज़दूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांवों की ओर लौटने को विवश हो गए। उस संकट ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में प्रवासी श्रमिकों के लिए एक सुदृढ़, संवेदनशील और समन्वित नीति की तत्काल आवश्यकता है।

सरकारी पहलः प्रयास हुए, लेकिन चुनौतियाँ शेष-पिछले कुछ वर्षों में केंद्र और राज्य सरकारों ने प्रवासी श्रमिकों के हित में कई योजनाएँ शुरू की हैं। "वन नेशन, वन राशन कार्ड" योजना ने श्रमिकों को देश के किसी भी हिस्से में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन प्राप्त करने का अधिकार दिया है। इसके अतिरिक्त, ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके। आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाएँ, श्रमिक आवास योजनाएँ तथा श्रम कानूनों में सुधार भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा सकते हैं। हालाँकि, जमीनी स्तर पर स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं कही जा सकती। बड़ी संख्या में श्रमिक जानकारी के अभाव, दस्तावेज़ी समस्याओं और राज्यों के बीच समन्वय की कमी के कारण इन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की निगरानी और सुरक्षा आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता- प्रवासी मज़दूर प्रायः अस्थायी और अनिश्चित रोजगार पर निर्भर रहते हैं। काम रुकते ही उनकी आय समाप्त हो जाती है और उनके सामने भोजन तथा जीवन-यापन का संकट खड़ा हो जाता है। ऐसे में खाद्य सुरक्षा को केवल कल्याणकारी योजना नहीं, बल्कि एक मौलिक आवश्यकता के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य में सस्ती राशन व्यवस्था, सामुदायिक रसोई और पोषण योजनाओं का विस्तार आवश्यक है। इसके साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी व्यापक होना चाहिए। दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, मातृत्व सहायता और बच्चों की शिक्षा जैसी सुविधाएँ प्रत्येक पंजीकृत प्रवासी श्रमिक तक प्रभावी ढंग से पहुँचनी चाहिए। आज भी हजारों श्रमिक खतरनाक परिस्थितियों में कार्य करते हैं, लेकिन दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में उन्हें पर्याप्त सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती।

सुरक्षा और सम्मान का प्रश्न- दूसरे राज्यों में काम करने वाले श्रमिक अक्सर भाषा, संस्कृति और स्थानीय पहचान के कारण भेदभाव और शोषण का सामना करते हैं। कई बार उन्हें न्यूनतम वेतन से कम भुगतान किया जाता है या असुरक्षित परिस्थितियों में काम कराया जाता है। महिला श्रमिकों की स्थिति और भी अधिक संवेदनशील है, जहाँ उन्हें आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार को श्रमिकों की सुरक्षा के लिए विशेष हेल्पलाइन, कानूनी सहायता केंद्र और त्वरित शिकायत निवारण तंत्र विकसित करना चाहिए। पुलिस और प्रशासनिक तंत्र को भी संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है ताकि प्रवासी श्रमिकों को सम्मानजनक व्यवहार और न्याय मिल सके।

राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक बोर्ड की आवश्यकता-वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह समय की माँग है कि केंद्र सरकार एक "राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक बोर्ड" का गठन करे। यह बोर्ड देशभर के प्रवासी श्रमिकों से संबंधित नीतियों और योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर सकता है।

सैयद इसरार हुसैन,
सामाजिक कार्यकर्ता

विद्या मंदिरों में लगते ताले

लेखिका- निर्मल रानी

देश के लगभग 21 लाख छात्रों का भविष्य पिछले दिनों उस समय फिर दांव पर लग गया जबकि नीट अर्थात नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट की राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा, पेपर लीक हो जाने के कारण रद्द कर दी गयी। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था एनटीए अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस मामले में स्वयं को ज़िम्मेदार मानते हुये परीक्षा रद्द करने की घोषणा की। पेपर लीक होने के चलते देश में पहले भी नीट परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। इसके लिए ज़िम्मेदार कोई भी हो परन्तु इससे सबसे बड़ा नुक़्सान उस मेहनतकश विद्यार्थी को हुआ है जिसने दिन रात एक कर परीक्षा दी और परीक्षा के परिणाम सुनने के बजाये उन्हें परीक्षा के रद्द होने जैसी मनहूस ख़बर सुनाई दी। इस घटना के बाद एक बार फिर हमारे देश की विद्या यहाँ के विद्यार्थियों तथा विद्यालयों के भविष्य को लेकर चर्चा छिड़ गयी है। एक तरफ़ तो नीट परीक्षा देने वाले जीव विज्ञान,वनस्पति विज्ञान,प्राणी विज्ञान,रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान के वे छात्र जो भविष्य में डॉक्टर,वैज्ञानिक,इंजीनियर आदि बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं,उनका भविष्य अधर में लटका दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ़ शिक्षा को लेकर सरकार का एजेंडा व उसकी प्राथमिकतायें भी कुछ और ही नज़र आ रही हैं। आज देश के विभिन्न राज्यों के विद्यालयों में अब भारतीय ज्ञान प्रणाली के नाम पर धर्म,अध्यात्म,कर्म काण्ड व पंडितों की शिक्षा दी जाने लगी है। यहाँ सरकारी और कुछ निजी स्कूलों में हिंदू धर्म, अध्यात्म, नैतिक मूल्यों, भारतीय ज्ञान प्रणाली और संबंधित ग्रंथों (जैसे भगवद्गीता, रामायण, वेद) की शिक्षा दी जा रही है और इससे संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत,मूल्य-आधारित शिक्षा, नैतिकता और सांस्कृतिक जागरूकता के नाम पर हो रहा है। हालांकि भारतीय संविधान (अनुच्छेद 28) सरकारी फ़ंड वाले स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है, लेकिन धर्मों के बारे में शिक्षा की अनुमति है जिसे आधार बनाकर धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ समर्थित व अन्य हिंदू संगठनों द्वारा संचालित स्कूलों में यह पहले से अधिक प्रचलित है। शिक्षा को लेकर हमारा देश इस समय एक ऐसे दुर्भागयपूर्ण दौर से गुज़र रहा है जबकि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर बैठे अनेक लोगों की शिक्षा, उनकी डिग्रियां असली हैं या नक़ली, विधान निर्माता शिक्षित है या अशिक्षित,इसतरह के सवाल उठ रहे हैं। उधर उच्च शिक्षा हासिल करने के लिये संपन्न लोग अपने बच्चों को पहले भी विदेश भेजा करते थे और आज भी भेजते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री व दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री स्व डॉ मनमोहन सिंह ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1957 में अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी ऑनर्स डिग्री हासिल की थी और ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय से 1962 में डी.फ़िल. की उपाधि ग्रहण की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू व राजीव गाँधी भी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। इसी तरह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण,ज्योतिरादित्य सिंधिया,राहुल गांधी,जयराम रमेश ,पी. चिदंबरम,कपिल सिब्बल,सुब्रमण्यम स्वामी,जयंत सिन्हा,रतन टाटा, आनंद महिंद्रा जैसे अनेकानेक राजनेता उद्योगपति व प्रतिष्ठित लोग हारवर्ड,कैम्ब्रिज,ऑक्सफोर्ड या अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। परन्तु हमारे प्रधानमंत्री की नज़रों में शायद इन विश्वविद्यालयों की डिग्रियों या यहाँ की पढ़ाई की उतनी अहमियत नहीं। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि एक तरफ़ वे लोग हैं जो हार्वर्ड की बात करते हैं, और दूसरी तरफ़ एक ग़रीब का बेटा है, जो अपनी कड़ी मेहनत (Hard work) से अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने तमिलनाडु में एक सभा में कहा था कि देश को विकास के लिए हार्वर्ड की नहीं, हार्ड वर्क की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री के अनुसार हार्वर्ड वालों से ज़्यादा दम हार्ड वर्क वालों में है। ज़रा सोचिये कि क्या पढ़ाई करना हार्ड वर्क की श्रेणी में नहीं आता ? जो बच्चा परीक्षा की तैयारी के लिये दिन रात एक किये रहता है,खाना पीना नींद आराम सब कुछ छोड़कर रोज़ 16 -18 घण्टे पढ़ाई करता है वह क्या हार्ड वर्क नहीं है ? निश्चित रूप से शिक्षा के प्रति शीर्ष सत्ता के इसी मनोभाव की वजह से ही आज देश के विद्या मंदिरों पर घोर संकट छाया हुआ है। विगत 10 वर्षों के दौरान भारत में लगभग एक लाख सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। यह कुल सरकारी स्कूलों में लगभग 8% की कमी है। आज दुर्भाग्यवश देश में सरकारी स्कूल्स की संख्या बढ़ने के बजाये 11.07 लाख से घटकर क़रीब 10.17 लाख हो गयी है। जबकि शुद्ध व्यवसायिक मॉडल वाले मंहगे निजी स्कूलों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। ग़ौरतलब है कि देश के सरकारी स्कूल्स में प्रायः साधारण परिवारों या ग़रीबों के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं जिनमें अधिकांश संख्या एस सी ,एस टी,ओ बी सी व अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की होती है। इनमें ज़्यादातर बच्चे किसानों,कामगारों व मेहनतकश मज़दूरों के होते हैं जो वास्तव में शिक्षा के हक़दार भी हैं और शिक्षा उनके भविष्य व जीविकोपार्जन के लिये बेहद ज़रूरी भी है। परन्तु सरकार की विद्या व विद्यालय विरोधी नीतियों के चलते देश में अब तक लगभग 65 लाख बच्चे स्कूल जाना छोड़ चुके हैं। सरकार द्वारा इस संबंध में यह तर्क दिया जाता है कि छात्रों की अपेक्षित संख्या न होने,संसाधन बचाने और बेहतर शिक्षा के कारण,इंफ्रास्ट्रक्चर व अध्यापकों की कमी या पोस्ट-कोविड प्रभाव कारण अनेक विद्यालयों का विलय पास पड़ोस के गांव में कर दिया गया है। जबकि उनकी दूरी 2 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक है। इतनी दूर बच्चों के स्कूल जाने के लिये न तो सरकार ने कोई उपाय किया है न ही अभिभावकों के पास कोई सामर्थ्य है। ख़ासकर अपनी बच्चियों को वैसे भी कोई मां बाप इतनी दूर के स्कूल नहीं भेजना चाहेगा।

भुवी झटक चुके हैं 21 विकेट

...लेकिन भारतीय टीम में वापसी के बारे में नहीं सोच रहे

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में बड़े-बड़े गेंदबाज संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन भुवनेश्वर कुमार का प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने 11 मैच में 21 विकेट लेकर पर्पल कैप पर कब्जा जमाए रखा है। ऐसे में रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गज खिलाड़ी ने भुवनेश्वर की भारतीय

टीम में वापसी की मांग कर दी है। हालांकि, भुवनेश्वर कुमार ने कहा है कि वह भारतीय टीम में वापसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार ने आरसीबी के सोशल मीडिया हैंडल पर कहा, 'मैं भारतीय टीम में वापसी के बारे में नहीं सोच रहा हूं। कई साल हो गए हैं जब मैंने लंबे समय के लक्ष्य रखना या बनाना बंद कर दिया है। जब भी मैंने ऐसा किया है तो यह मेरे लिए कभी काम नहीं आया। मैं खुश हूं कि 200 मैच खेले और पावरप्ले और डे ओवर इतने सारे विकेट लिए। मुझे लगता है कि यह सब उन कामों का इनाम है जो मैंने इतने सालों में किए हैं। अच्छे साल भी रहे हैं और बुरे साल भी। सच कहूं तो इस समय मुझे कुछ खास महसूस नहीं हो रहा है। बेशक, अगर मैं कहूं कि बाद में मुझे ऐसा महसूस नहीं होगा तो मैं झूठ बोलूंगा।

आईपीएल के बाद मुझे काफी लंबा ब्रेक मिलता है

भुवनेश्वर कुमार ने कहा, 'मुझे पता है कि 2026 अच्छा जा रहा है। मुझे विकेट मिल रहे हैं, लेकिन मैं वही सब कर रहा हूं जो मैं पहले भी कर रहा था। बेशक मैं कह सकता हूं कि ट्रेनिंग थोड़ी ज्यादा हो गई है या शायद कुछ चीजें बेहतर हुई हैं क्योंकि मैं देश के लिए नहीं खेल रहा हूं। सबसे अच्छी बातों में से एक यह है कि आईपीएल के बाद मुझे काफी लंबा ब्रेक मिलता है।

विराट आलोचना नहीं झेल पाते

- पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने टॉस के दौरान का बताया वाकया

नई दिल्ली। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर का मानना ??है कि विराट कोहली आलोचना नहीं झेल पाते हैं। उनका दावा है कि कोहली अपने बारे में कही गई हर बात को पढ़ते और सुनते हैं। मांजरेकर ने उन घटनाओं के बारे में बताया जब टॉस के समय कोहली ने आलोचना के बाद उन्हें 'ठंडा' जवाब दिया था। मांजरेकर ने कहा कि कोहली कहते हैं कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं या क्या सोचते हैं, लेकिन भारत के पूर्व कप्तान मैदान पर अपने प्रदर्शन के जरिए आलोचना या नकरात्मकता का जवाब देना चाहते हैं। मांजरेकर ने स्पोर्टस्टार के इनसाइट एज पॉडकास्ट पर कहा,'कोहली ऐसे इंसान हैं जो आलोचना नहीं झेल पाते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें पता चल जाता है कि उनके बारे में क्या कहा जा रहा है क्योंकि मेरा उनके साथ एक कप्तान और एक खिलाड़ी के तौर पर अनुभव रहा है। अचानक एक दिन मैंने उन्हें टॉस के समय या कहीं और बहुत ठंडा पाया और मुझे लगा शायद उन्होंने अपने बारे में कही गई कोई बात सुन ली है।'

आलोचना से बड़ा शतक जड़ने के लिए प्रेरणा

मांजरेकर ने कहा, 'वह उन लोगों में से एक है जो कहते रहे हैं कि हमें इस बात की परवाह नहीं है कि लोग क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं, लेकिन वह बहुत भावुक भी हैं। शायद यह एक अच्छी बात भी है क्योंकि अगर वह इस तरह की आलोचना या कुछ नकारात्मक सुनते हैं तो इससे उन्हें बड़ा शतक जड़ने के लिए प्रेरणा मिलती है।' मांजरेकर ने मैदान पर कोहली की ऊर्जा की तारीफ की और कहा कि इससे टीम का हौसला बढ़ाने में मदद मिलती है। विराट कोहली की कप्तानी में हर खिलाड़ी को विराट कोहली जैसा बनना था मांजरेकर ने कहा, 'कप्तान के तौर पर उनके बारे में अच्छी बात यह थी कि जब चीजें खराब चल रही थीं जब उन्हें पता था कि पिच या गेंदबजी के साधनों को देखते हुए वे विकेट नहीं ले पाएंगे तब भी वे यह पक्का करते थे कि टीम जोश में रहे। मैदान पर ऊर्जा बनी रहे। उन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि चीजें होंगी। मुझे लगता है कि यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। मेरा हमेशा से मानना ??रहा है कि टीम कप्तान जैसा होता है वैसी ही होती है। विराट कोहली की कप्तानी में हर खिलाड़ी को विराट कोहली जैसा बनना था। अगर कोई मैदान पर जाकर थोड़ा भी ढीला दिखता तो वह अगला टेस्ट मैच नहीं खेल पाता। इसलिए सभी ने विराट के आक्रमकता को अपनाया।'

गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया

पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची GT

नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में मंगलवार 12 मई 2026 को गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच खेला गया। आईपीएल 2026 के 56वें मैच में गुजरात टाइटंस ने हरफनमौला प्रदर्शन करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस की यह लगातार पांचवीं जीत है। गुजरात टाइटंस अब आईपीएल 2026 की अंक तालिका में पहले स्थान पर है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे स्थान पर बनी हुई है। लगातार पांचवीं जीत के बाद गुजरात टाइटंस के अब 12 मैच में 16 अंक हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के 12 मैच में 14 अंक हैं। गत चैंपियन आरसीबी के 11 मैच में 14 अंक हैं।

- **सनराइजर्स हैदराबाद 86 रन पर ढेर हो गई-** सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने मंगलवार रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेले गए मैच में टॉस जीता और फील्डिंग चुनी। साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर के अर्धशतकों की मदद से शुभमन गिल की अगुआई वाली गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 168 रन बनाये। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद 14.5 ओवर में 86 रन पर ढेर हो गई।
- **SRH ने 60 रन पर गंवा दिये थे सात विकेट-** एक समय सनराइजर्स हैदराबाद ने महज 60 रन पर ही 7 विकेट गंवा दिये थे। कगिसो रबाडा प्लेयर ऑफ द मैच चुने गये। कगिसो रबाडा ने सनराइजर्स हैदराबाद के शीर्ष क्रम की बखिया उधेड़ते हुए 4 ओवर में 28 रन देकर तीन विकेट लिए, जबकि जेसन होल्डर ने 4 ओवर में 20 रन देकर तीन विकेट चटकाये।

व्यापार

गौतम अडानी का घटा रुतबा, 6.07 अरब डॉलर का झटका, मुकेश अंबानी टॉप-20 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर

नईदिल्ली, एजेंसी। दुनिया के अमीरों में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी का रुतबा थोड़ा कम हुआ है। मंगलावर को ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट हुई। इस कारण उनकी दौलत

6.07 अरब डॉलर कम हो गई। अब अडानी ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स में 17वें पायदान से खिसककर 18वें पर पहुंच गए हैं। दूसरी ओर रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी दुनिया के अरबपतियों की टॉप-20 लिस्ट से बाहर हो गए हैं। अंबानी ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के 21वें पायदान पर पहुंच गए है। माइकल डेल मंगलवार को दौलत गंवाने वाले अरबपतियों में नंबर एक रहे। इन्हें 21 अरब डॉलर का झटका लगा है। अडानी का अब नेटवर्थ 102 अरब डॉलर रह गया है। दूसरी ओर मुकेश अंबानी की दौलत 89.3 अरब डॉलर रह गई है।

दुनिया के टॉप-10 अमीरों के नेटवर्थ में क्या हुआ बदलाव

टेस्ला के शेयरों में गिरावट की बदौलत एलन मस्क की दौलत में मंगलवार को 8.35 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई। इस गिरावट के साथ ही उनका नेटवर्थ 688 अरब डॉलर पर आ गया है।

शेयर बाजार के इंडेक्स बने हैं रोलर कोस्टर, पेनी स्टॉक सुबह ही जा फंसा अपर सर्किट में

मुंबई, एजेंसी। भारतीय शेयर बाजार के इंडेक्स आज सुबह से ही रोलर कोस्टर बना हुआ है। बीएसई का सेंसेक्स जब खुला तो 119.90 अंक नीचे था। लेकिन थोड़ी ही देर में यह करीब 400 अंक ऊपर चला गया। इसी बीच गिरावट आई तो लगभग 400 से ज्यादा अंक नीचे चला गया। लेकिन इस स्थिति में भी इंडस्ट्रियल केमिकल की लॉजिस्टिक्स और ट्रेडिंग कंपनी ए-1 लिमिटेड (बीएसई - 542012) के शेयर सुबह ही अपर सर्किट में जा फंसे।

ए-1 केमिकल ने कल ही वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही का परिणाम जारी किया है। शेयर बाजार को दी गई नियामकीय जानकारी के अनुसार मार्च 2026 को समाप्त पूरे वर्ष के लिए कंपनी ने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन किया है। कंपनी ने चौथी तिमाही में 4.36 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया है। यह एक साल पहले की इसी तिमाही के के 0.84 करोड़ रुपये के मुकाबले 417.11 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्शाता है। इस दौरान ऑपरेशनल रेवेन्यू 145.27 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले के 109.62 करोड़ रुपये के मुकाबले 32.51 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। मार्च 2026 को समाप्त हुए वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने 5.99 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो वित्त वर्ष 2024-25 के 3.65 करोड़ रुपये की तुलना में 64.12 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। इस दौरान ऑपरेशनल रेवेन्यू 342.91 करोड़ रुपये रहा, जो एक वर्ष पहले के 331.49 करोड़ रुपये के मुकाबले 3.44 प्रतिशत की वृद्धि है।

क्या रही शेयर की चाल: ए-1 लिमिटेड के शेयर बीएसई में कल 10.26 रुपये पर बंद हुए थे। आज सुबह इसके शेयर 10.77 रुपये पर खुले जो कि कल के मुकाबले पांच फीसदी ज्यादा है। कारोबार के दौरान इसके शेयर थोड़ी देर के लिए 10.76 रुपये पर आए, लेकिन तुरंत ही यह फिर 10.77 रुपये पर चले गए। इस कंपनी के शेयर का सर्किट लिमिट पांच फीसदी का है। मतलब कि यह शेयर सुबह ही अपर सर्किट में फंस गए। पेनी ब्रिटिश मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग की एक इकाई है। शेयर बाजार में पेनी स्टॉक का अर्थ उन लिस्टेड कंपनियों के शेयर से लगाए जाते हैं, जिनकी कीमत बहुत कम होती है। आमतौर पर इन कंपनियों के शेयर का दाम एक रुपया से 50 रुपये के बीच होता है। ये शेयर होते तो सस्ते हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। इनमें उच्च अस्थिरता और कम लिक्विडिटी भी होती है। लेकिन कम दाम के कारण इनमें कम समय में तेजी से रिटर्न देने की क्षमता भी होती है। इसलिए ढेर सारे निवेशक इन्हें ढूंढते रहते हैं।

महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल

इस लॉजिस्टिक कंपनी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने बताया है कि उसके 90 प्रतिशत से अधिक व्हीकल अब डेट-फ्री हैं। इसले लक्ष्य तय किया है कि अक्टूबर 2026 तक उसके सभी व्हीकल पूरी तरह से डेट-फ्री हो जाएंगे। ऋण-मुक्त बेड़े में परिवर्तित हो जाएगी। साथ ही कंपनी अपने मौजूदा बेड़े में 10 मल्टी-एक्सल टैंकर जोड़कर अपनी लॉजिस्टिक्स क्षमताओं को और बढ़ा रही है। इस विस्तार के साथ, कंपनी के स्वामित्व वाले बेड़े में वाहनों की कुल संख्या बढ़कर 71 हो जाएगी, जिससे यह बढ़ती ग्राहक मांग को बेहतर ढंग से पूरा करने और सभी बाजारों में समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने में सक्षम होगी। बेड़े के आकार में वृद्धि से तृतीय-पक्ष ट्रांसपोर्टरों पर निर्भरता कम होने।

- खड़ा किया 45 करोड़ का करोबार, साधारण से काम से भी कामयाबी की बुलंदियों को छुआ जा सकता है

लैब से कड़ाही तक, साइंटिस्ट पति-पत्नी ने नौकरी छोड़कर बेचे समोसे

नई दिल्ली, एजेंसी। निधि और शिखर सिंह बेंगलुरु के रहने वाले हैं। इस कपल ने साबित कर दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो साधारण से काम से भी कामयाबी की बुलंदियों को छुआ जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में अपनी जमी-जमाई मोटी सैलरी वाली जॉब छोड़कर दोनों ने कारोबार की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। स्टार्टअप को बड़ा करने के लिए अपना घर तक बेच डाला। इसका नाम 'समोसा सिंह' है। आज यह ब्रांड भारतीय स्नैक्स की दुनिया में बड़ा नाम बन चुका है। इसने पारंपरिक स्वाद को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर एक नई पहचान हासिल की है। इसका टर्नओवर 45 करोड़ रुपये पहुंच गया है। आइए, यहां निधि और शिखर सिंह की सफलता के सफर के बारे में जानते हैं। साल 2015-16 की बात है। निधि और शिखर ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने सफल करियर को छोड़कर समोसे बेचने का मन बनाया। इससे उनके कई करीबी हैरान रह गए। उन्होंने दोनों को खूब

टोका। उनका मानना था कि एक सुरक्षित और शानदार जिंदगी को छोड़कर इस तरह का रिस्क लेना समझदारी नहीं है। हालांकि, इस कपल ने एक फूड कोर्ट में गौर किया था कि समोसा भारत का सबसे पसंदीदा स्नैक तो है। लेकिन, मार्केट में कोई बड़ा ब्रांडेड प्लेयर नहीं है। इसी कमी को पूरा करने के लिए शिखर ने पहले नौकरी छोड़ी। उनका मानना था कि 'बैकअप' होने पर इंसान अपना 100 प्रतिशत नहीं दे पाता।

साइंस बैकग्राउंड से होने के कारण कपल ने समोसे को सिर्फ एक रेसिपी के बजाय विज्ञान की तरह देखा। उनकी सबसे बड़ी चुनौती समोसे का 'सोगी' (नरम या गीला) होना था। ऐसा डिलीवरी के दौरान अक्सर हो जाता है। अपनी बायोटेक स्किल्स का इस्तेमाल करके उन्होंने विशेष रोलर्स और तकनीक विकसित की। यह मैदे के 'ग्लूटेन बॉन्ड्स' को तोड़ देती है। इस तकनीक की मदद से उनके समोसे डिलीवरी के 6 घंटे बाद भी उतने ही कुरकुरे रहते हैं, जितने कड़ाही से निकलने पर होते हैं। सफर की शुरुआत बेंगलुरु में महज 300 वर्ग फीट की एक छोटी सी रसोई और एक रसोइए के साथ हुई थी। शुरू में शिखर खुद डिलीवरी करते थे। निधि ग्राउंड लेवल पर मैनेजमेंट देखती थीं। व्यापार को बड़ा करने और मांग को पूरा करने के लिए एक समय ऐसा आया जब उन्होंने बिना डरे अपना खुद का मकान तक बेच दिया ताकि निवेश की कमी न हो। उनकी मेहनत रंग लाई।

पश्चिम एशिया संकट के बीच बढ़ी खुदरा महंगाई, अप्रैल में 3.48 प्रतिशत पर पहुंची

नई दिल्ली, एजेंसी। सोने-चांदी के आभूषणों और रसोई से जुड़े कुछ उत्पादों के दाम बढ़ने से अप्रैल में खुदरा महंगाई की दर मामूली रूप से बढ़ी है। यह बढ़कर 3.48 फीसदी हो गई। मंगलवार को आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। पश्चिम एशिया में जारी घमासान के बीच महंगाई का बढ़ना अच्छा संकेत नहीं है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2024 को आधार मानकर किए गए कैलकुलेशन के आधार पर खुदरा महंगाई दर अप्रैल में 3.48 फीसदी रही। मार्च में यह 3.40 फीसदी थी। इसके पहले फरवरी में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (सीपीआई) पर आधारित खुदरा महंगाई दर 3.21 फीसदी जबकि जनवरी महीने में 2.74 फीसदी रही थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, खाद्य उत्पादों की कीमतें बढ़ने से अप्रैल में खाद्य महंगाई दर सालाना आधार पर बढ़कर 4.2 फीसदी हो गई। मार्च में यह 3.87 फीसदी थी। कीमतों में सबसे अधिक 144.34 फीसदी की बढ़ोतरी चांदी से बने आभूषणों में दर्ज की गई। इसके बाद नारियल-कोपरा (44.55 फीसदी), सोना, हीरा और प्लैटिनम आभूषण (40.72 फीसदी), टमाटर (35.28 फीसदी) और फूलगोभी (25.58 फीसदी) का स्थान रहा। हालांकि, अप्रैल में आलू, प्याज, कार-जीप, मटर और एयर कंडीशनर की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। पिछले महीने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए खुदरा महंगाई का अनुमान जताया था। आरबीआई ने इसके 4.6 फीसदी रहने के अनुमान जाहिर किए थे। वहीं, पहली तिमाही के लिए चार फीसदी महंगाई का अनुमान था। आरबीआई ने कहा था कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण ऊर्जा संसाधनों की ऊंची कीमतें और संभावित 'अल नीनो' प्रभाव के कारण महंगाई बढ़ने का जोखिम है।आरबीआई अपनी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा के दौरान खुदरा महंगाई के आंकड़ों को ही ध्यान में रखकर निर्णय करता है। एनएसओ के आंकड़ों से पता चलता है कि अप्रैल के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महंगाई की दर 3.74 फीसदी और 3.16 फीसदी दर्ज की गई।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेलः- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)